

खबर संक्षेप

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दे दी है। अब विदेशी निवेशक ऑटोमैटिक रूट के जरिए भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों में पूरी हिस्सेदारी ले सकेंगे, हालांकि एलआईसी के लिए निवेश की सीमा 20% पर ही बरकरार रखी गई है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बीमा अधिनियम-1938 के प्रावधानों के अधीन होगा। *एजेंसी*

हैदराबाद में भुजंगासन में बना विश्व रिकॉर्ड

हैदराबाद। यहां योग महोत्सव में हजारों लोगों ने भाग लेकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों को नई ऊर्जा दी। मुख्य आयोजन से 50 दिन पहले हुए कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों की भागीदारी रही। कान्हा शांति वन्य में 6,000 से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ भुजंगासन का अभ्यास किया। यह उपलब्धि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई। *एजेंसी*

प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रसून जोशी एक जाने-माने क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं, जिनका साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। *एजेंसी*

पाक में पेट्रोल 458 प्रति लीटर, 5 दिन का स्टॉक

इस्लामाबाद। मिडिल ईस्ट में बने तनाव के हालात के चलते पाकिस्तान उर्जा संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा है कि हमारे पास कोई रणनीतिक तेल का भंडार नहीं है। हमारे पास केवल व्यावसायिक भंडार है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान रुपए में 321.17 से बढ़कर 458.41 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इधर मलिक ने बताया कि अब डीजल की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं। डीजल पर लेवी को घटाकर शून्य कर दिया गया है। *एजेंसी*

यहां बैंक लोन भी देता है गोदाम में रखे पनीर पर, खाने से पहले 12 से 40 महीनों तक होती है एजिंग

उत्तरी इटली में सोने-चांदी से कम नहीं हैं पार्मिजियानो रेज्जियानो चीज के ये चक्के

सैटल डेस्क►► रोहतक किसी देश की सबसे मूल्यवान संपत्तियां क्या होती हैं सोना, चांदी, मुद्रा? लेकिन उत्तरी इटली के एमिलिया-रोमाना क्षेत्र में इसका उत्तर कुछ अलग ही नजर आता है। यहां विशाल व तापमान-नियंत्रित गोदामों में संपत्ति का एक बेहद अनोखा रूप संग्रहित है। यहां पार्मिजियानो रेज्जियानो चीज के लाखों गोल चक्के धीरे-धीरे परिपक्व (एजिंग) होते हुए समय के साथ और अधिक मूल्यवान बनते जाते हैं। दर्शकों को ये इमारतें शांत चीज के कैथेड्रल जैसी लगती हैं, लेकिन इटली के डेयरी उद्योग के लिए ये एक



आर्थिक जीवनरेखा हैं। पार्मिजियानो रेज्जियानो एक खास पनीर है। इसे केवल इटली के एक विशेष क्षेत्र में सिर्फ तीन चीजों दूध, नमक और रेनेट से बनाया जा सकता है। हर एक चक्के को बेचने से पहले कम-से-कम 12 महीने तक परिपक्व (एज) किया जाना अनिवार्य है, जबकि कई को 24, 36 या 40 महीनों तक रखा जाता है।

हरिभूमि

हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

फिर बदला मौसम, 7 मई तक बारिश-आंधी का अलर्ट

◀ पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर
◀ 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं
◀ बार-बार बदल रहे मौसम से गर्मी से मिली राहत
◀ 41.1 डिग्री के साथ हिसार रहा राज्य में सबसे गर्म जिला

हरिभूमि टीम►► हरियाणा

हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 7 मई तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। 3, 4 और 5 मई को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से यह बदलाव आया है। प्रदेश में 4 मई को राज्य के अनेक स्थानों तथा 5 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लोगों को एक सप्ताह तक गर्मी से भी राहत मिली रहेगी।



3 और 6 मई को भी अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 एवं 6 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, 4 और 5 मई को कुछ जिलों में हवाओं की गति बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।

अमेरिका और ईरान में तनाव बरकरार, फिर जंग जैसे हालात बने

ट्रंप के वादे खोखले, हम युद्ध के लिए तैयार : ईरान

एजेंसी ►► तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध के हालात बन गए हैं। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने आशंका जताई है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और अगर अमेरिका कोई गलत कदम उठाता है, तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का पालन नहीं करता। उसके सारे वादे खोखले हैं। असदी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और कदम ज्यादातर दिखावटी और मीडिया के लिए होते हैं। उनका मकसद पहले तेल की कीमतों को गिराने से रोकना और दूसरा अपनी बनाई हुई मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। *(पेंज-8 भी देखें)*



दोनों की मांगों में अंतर इसलिए नहीं बन रही बात

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी भी फंसी हुई है। दोनों देशों की मांगें एक-दूसरे से काफी अलग हैं। दोहा के प्रोफेसर मोहम्मद एलमसी ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में हालात ज्यादा नहीं बदले हैं और बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने कहा कि ईरान ने 10 मांगें रखी हैं, जबकि अमेरिका ने 15 मांगें रखी हैं। इन दोनों को साथ देखने पर साफ है कि दोनों देशों के बीच बड़ा फर्क है। एलमसी के मुताबिक, इसी वजह से बातचीत रुकी हुई है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अमेरिका को लगता है कि ईरान जल्द ही तेल से जुड़ी बड़ी समस्या में फंसेंगे वाला है। हालांकि एलमसी का मानना है कि यह सोच पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसे उपाय कर लिए हैं जिससे वह अभी कुछ समय तक हालात संभाल सकता है।

ईरानी प्रस्ताव को ट्रंप ने कर दिया था खारिज

ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि उनके नए प्रस्ताव में पहले होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की बात है, जबकि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में की जाएगी। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ईरान का मानना है कि परमाणु मुद्दे को बाद में रखने से समझौता करना आसान हो सकता है। यह प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत अगर समझौता होता है, तो युद्ध खत्म हो जाएगा और इजराइल और अमेरिका दोबारा हमला नहीं करने का वादा करेंगे।

ट्रंप और चिनफिंग की वार्ता में शामिल रहेगा होर्मुज का मुद्दा

चीन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत फू कॉन्ग ने कहा है कि ईरान-अमेरिका में युद्धविराम बनाए रखना और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना अभी सबसे जरूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज बंद रहता है, तो यह मुद्दा शी चिनफिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में प्रमुख रहेगा। फू कॉन्ग के मुताबिक, यह मामला दोनों देशों की मौटिंग के एजेंडों में सबसे ऊपर हो सकता है।

भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज

भारत से जुड़ा एक सुपरटैंकर, जिसमें खाना पकाने वाली गैस (एलपीजी) भरी है, ने होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। माशेल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर 'सर्व शक्ति' करीब 45,000 टन एलपीजी लेकर शनिवार को इस समुद्री रास्ते से गुजरना। जहाज की मुकद्दत ट्रैकिंग डेटा के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह टैंकर ईरान के लारक और केशम द्वीपों के पास से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है।

हिंसा और गड़बड़ियों की शिकायत पर फैसला



प. बंगाल की फालता सीट पर वोटिंग रह, अब 21 को मतदान

कोलकाता (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फालता सीट पर वोटिंग रद्द कर दी है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान इंदीपम में गड़बड़ी और हिंसा की खबर आई थी। चुनाव आयोग ने सभी 285 पोलिंग बुथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने का निर्देश दिया है। रिजल्ट 24 मई को आएगा। इसी विधानसभा के एक बुथ पर इंदीपम में भाजपा की बटन के आगे टेप लगा मिला था। इससे पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल में मंगराहाट पश्चिम के 11 बुथों और डायमंड हार्बर के 4 बुथों में दोबारा मतदान हुआ। दोनों विधानसभा क्षेत्र के कुल 15 बुथों पर करीब 90% वोटिंग हुई। साउथ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब वे इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई है। वहीं, टीएमसी ने आरोप लगाया कि मंगराहाट के बुथ नंबर 127 पर सुरक्षाबलों ने हमारे कैप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्टूटिंग एजेंडस को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। *(पेंज-4 भी देखें)*

अमेरिका-जर्मनी में तनावती

नाराज ट्रंप ने 5000 सैनिक वापस बुलाए

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी होगी। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रैंज़िस्क मर्ज के बीच बयानबाजी के बाद सामने आया है। मर्ज ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका के पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि वह इस जंग से बाहर कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत को टालने में माहिर है और अमेरिका को बिना नतीजे के इस्लामाबाद तक आना-जाना पड़ा। इससे अमेरिका को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा। इससे ट्रंप नाराज हो गए थे। उन्होंने मर्ज को लेकर कहा कि वे बहुत खराब काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना अच्छी बात है।

सुरक्षा, क्षमता होगी सुदृढ़

रेलवे में 895.30 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। रेलवे ने रेलवे पुलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत और मेट्रो रेल की विद्युत प्रणालियों को उन्नत बनाने के लिए 895.30 करोड़ की प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य सुरक्षा, क्षमता और संचालन दक्षता को बेहतर बनाना है। कोलकाता मेट्रो के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए 671.72 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है। 7 नए ट्रेक्शन सब-स्टेशन बनाए जाएंगे और मौजूदा 11 केवी बिजली प्रणाली को 33 केवी में अपग्रेड किया जाएगा।



7 नए ट्रेक्शन सब-स्टेशन बनाए जाएंगे

सायरन की आवाज सुनाई दी

देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ आया अलर्ट नैसेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में शनिवार सुबह 11:45 बजे कई मोबाइल फोन पर एकसाथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी-अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए, तो कई कन्फ्यूज। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी एनडीएमए ने भेजा था। एनडीएमए ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया।



सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की

पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची

भाजपा में आने वाले संदीप पाठक पर एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो एफआईआर दर्ज हुई हैं। यह केस भ्रष्टाचार और शोषण से जुड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संदीप पाठक केस दर्ज होने की खबर बाहर आने से पहले दिल्ली स्थित अपने घर के पिछले दरवाजे से निकल गए। दावा किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में बैठकर संदीप निकले, वह राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के नाम पर रजिस्टर्ड है।



अशोक मित्तल की गाड़ी में पिछले दरवाजे से निकले

महाराष्ट्र के पुणे में वारदात

4 साल की बच्ची से दुष्कर्म पत्थर से कुचलकर हत्या

पुणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 65 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची पुणे के भोर तहसील में रहने वाली अपनी नानी के यहां गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। भीमराव कांबले (आरोपी) शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के पास बने तबले में ले गया। वहां बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी।



65 साल का आरोपी गिरफ्तार, नानी के घर आई थी बच्ची

कड़कड़डूमा कोर्ट का मामला

दिल्ली में जज ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के 30 साल के युवा जज अमन कुमार शर्मा ने ग्रीन पार्क स्थित अपने आवास पर बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर हुई। उनकी पत्नी भी जज हैं। आत्महत्या करने का कारण पता नहीं लग सका। वे दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित डीएलएसए में सचिव के पद पर तैनात थे। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच कर रही है।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में थे सचिव

राजस्थान की ओबीसी महिला की हरियाणा में बीसी-बी प्रमाणपत्र नवीनीकरण याधिका खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

विवाह के बाद पति के राज्य में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ



कोर्ट बोला-जाति जन्म से तय होती है, विवाह से नहीं बदलती

किया जा सकता। याचिकाकर्ता रेवाड़ी निवासी एकता यादव ने हाईकोर्ट में मांग की थी कि हरियाणा सरकार को उनका बीसी-बी प्रमाणपत्र नवीनीकृत करने और 10 अगस्त 2025 के कानूनी नोटिस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनका दावा गलत तरीके से अस्वीकार किया गया।

सरकार ने ये दिया तर्क

हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि 22 मार्च 2022 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होता है, तो वह केवल अपने मूल राज्य में मान्य जाति श्रेणी का लाभ ले सकता है, न कि पिछले या प्रवास के आधार पर नए राज्य में उसी श्रेणी का दावा कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचना के पैरा 3(4) के अनुसार किसी अन्य जाति या वर्ग के व्यक्ति से विवाह कर लेने मात्र से किसी महिला की जातीय श्रेणी परिवर्तित नहीं होती।

भाखड़ा बांध का जलस्तर सामान्य से 36 फुट अधिक, हरियाणा को मिलेगा पर्याप्त पानी

गर्मियों को लेकर तैयारी ■ मुख्यमंत्री ने ली सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक ■ हरियाणा ने अपने हिस्से का 75% जल ही उपयोग किया

हरिभूमि ब्यूरो►► चंडीगढ़

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार भाखड़ा बांध में पानी की स्थिति बेहतर होने से प्रदेश में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश के सभी हिस्सों में पेयजल आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। शनिवार को सचिवालय में जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पेयजल व सिंचाई के पानी की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में भाखड़ा बांध का जलस्तर सामान्य से करीब 36 फुट अधिक है। साथ ही हरियाणा अपने हिस्से का अब तक केवल 75-76 प्रतिशत पानी ही उपयोग कर पाया है, जिससे आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नहरों से जुड़े सभी जलघरों और तालाबों को भरकर रखा जाए ताकि किसी भी क्षेत्र में पेयजल की कमी न हो। जहां ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति होती है, वहां खराब



गांवों में 6500 जलघर, सभी में पर्याप्त पानी

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 4000 एकल गांव आधारित जलघर हैं जबकि 2500 जलघर एक से अधिक गांवों के लिए हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी जलघर नहरों से जुड़े हैं और फिलहाल इनमें पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने नहरों की सफाई, मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और यह सभी कार्य त्वरित गति से करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

ट्यूबवेल को तुरंत ठीक करवाने के निर्देश भी दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर टैंकों के माध्यम से भी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में नहरों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर जलस्तर का पूरा लाभ उठाते हुए पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को

मजबूत बनाया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने जल परियोजनाओं को लेकर जल्द ही केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ बैठक करने की बात भी कही, जिससे भविष्य की जल आवश्यकताओं की बेहतर योजना बनाई जा सके। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा ने पानी के उपयोग में संयम दिखाया हम अतिरिक्त पानी नहीं देंगे : भगवंत मान

योगेंद्र शर्मा►► चंडीगढ़

हरियाणा और पंजाब के बीच संभावित जल संकट को लेकर खींचतान से पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पानी के संयमित उपयोग की अपील तेज कर दी है। उन्होंने बार-बार हरियाणा को सलाह दी है कि पानी का इस्तेमाल संतुलित और सावधानीपूर्वक किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब 21 मई तक हरियाणा को उसके निर्धारित कोटे के अनुसार पानी दे रहा है, लेकिन इससे अधिक पानी देना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि हरियाणा अब तक अपने हिस्से का लगभग 70-75 प्रतिशत पानी ही उपयोग कर पाया है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

उन्होंने इस पर हरियाणा की सराहना भी की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा।

पंजाब सीएम ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर भी पानी के संयमित उपयोग और बेहतर जल प्रबंधन की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि 21 मई तक उपलब्ध पानी का उपयोग सावधानी से किया जाए, इसके बाद ही अगली खेप कोटे के अनुसार दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और राज्य अब अपने किसानों और लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पहली बार पंजाब के पानी को राज्य के भीतर अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि हरियाणा ने अब तक पानी के उपयोग में संयम दिखाया है। उन्होंने फिजूलखर्ची रोकने और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

रेवाड़ी में जन आशीर्वाद रैली में बोले मुख्यमंत्री ट्रिपल इंजन की सरकार हर संकल्प को पूरा करेगी : नायब



रेवाड़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को रेवाड़ी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि रेवाड़ी के विकास के लिए एक-एक वोट कमल के निशान पर डालकर भाजपा प्रत्याशियों को

भारी बहुमत से जिताएँ। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को जिस तरह से गिराने का काम किया है उसी तरह से 10 मई को कांग्रेस को भी गिराने का काम करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने 21 संकल्प लिए हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद इन सभी संकल्पों को ट्रिपल इंजन की सरकार तीन गुणा तेज गति से पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री ने धारुहेड़ा में रोड शो निकाला

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धारुहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में रोड शो कर पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी सत्यनारायण 'अजय जांगड़ा' के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगा। सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों ने



पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया तथा लोगों से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो से पहले मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क में पहुंचकर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन किया।

खबर संक्षेप

कर्मचारी हड़ताल से सफाई व्यवस्था प्रभावित

फरीदाबाद। नगर निगम व फायर विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दूसरे दिन भी सफाई, सीवर व डोर टू डोर और रात्रि में होने वाला सफाई का काम बुरी तरह प्रभावित रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह बालगुहेर की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया। जिसका संचालन सचिव महेंद्र कुडिया ने किया। आम सभा को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व मजदूर संगठन सीटू के महासचिव जय भगवान ने संबोधित किया और अपने संगठनों की तरह से हड़ताल व मांगों का पुरजोर समर्थन किया।

चाकू मारकर युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। रोशन नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 1 अप्रैल की रात जैतपुर एक्सटेंशन, दिल्ली निवासी 25 वर्षीय मानस की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता की शिकायत पर थाना पल्ला में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस चौकी नवीन नगर की टीम जांच में जुटी थी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 1 मई को मुख्य आरोपी अमन, निवासी शिवम कॉलोनी इस्माइलपुर, फरीदाबाद को सेक्टर-91 स्थित गुग्रां विल्डर इलाके से काबू किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

प्रधानमंत्री से मिले राज्यपाल प्रो. घोष



प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने हरियाणा के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की प्रगति, चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं और अन्य प्रमुख विकास कार्यों से अवगत करायी। इस अवसर पर शंख चटर्जी ने राज्यपाल और प्रथम महिला के साथ प्रधानमंत्री को अपनी दो लिखित पुस्तकें भेंट कीं।

हर जिले में शव वाहन अनिवार्य, रिपोर्ट तलब

हरिभूमि ब्यूरो►► चंडीगढ़

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने मृतकों की गरिमा से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के स्वास्थ्य व प्रशासनिक तंत्र को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों द्वारा शव को ठेले पर ले जाने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मृत्यु के बाद भी गरिमा का अधिकार सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसे प्रणालीगत कमी मानते हुए आयोग ने गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क शव परिवहन नीति बनाने के निर्देश दिए। आयोग ने अस्पतालों में शव वाहन सेवा की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने, स्टाफ को संवेदनशील बनाने

मृतकों की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : हरियाणा मानवाधिकार आयोग

और प्रत्येक जिले में कम से कम एक कार्यशील शव वाहन उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतशालाओं की सुरक्षा बढ़ाने और स्वास्थ्य व पुलिस विभाग के समन्वय पर भी जोर दिया गया है।

आयोग ने सभी सिविल सर्जनों से रिपोर्ट तलब की है, जिसे 13 अगस्त 2026 से एक सप्ताह पहले प्रस्तुत करना होगा। आयोग ने कहा कि किसी भी नागरिक की मृत्यु के बाद उसकी गरिमा आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं हो सकती।

निकाय चुनाव : आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग सख्त

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने बताया कि नगर निकायों में होने वाले सामान्य एवं उप-चुनावों के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के ध्यान में आया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यव पर्यवेक्षकों तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघनों को तुरंत रोकना जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखें।

चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यव पर्यवेक्षकों तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघनों को तुरंत रोकना जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखें।

मंडियों में अब तक 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य में रबी खरीद सीजन 2026 - 27 के अंतर्गत प्रदेश भर की मंडियों और खरीद केंद्रों में सफलतापूर्वक सरसों और गेहूं की खरीद की जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी खरीद 2026 - 27 के दौरान 1 मई तक लगभग 83,87,482.40 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 80,18, 012.95 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। राज्य में रबी खरीद सीजन 2026 - 27 के दौरान सरसों की खरीद 28 मार्च एवं गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से आरम्भ हुई थी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने हेतु इस बार किये गए नए प्रावधानों जैसे किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, मंडियों/खरीद केंद्रों की जियो फेंसिंग, कैमरे इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

विकास को लेकर बढ़ी जागरूकता : कल्याण

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द कल्याण ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विगत 11 सालों में न केवल घरीडा क्षेत्र, बल्कि पूरे प्रदेश में जनक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और समाज में जागरूकता भी बढ़ी है। युवाओं को मैरिट पर नौकरी मिल रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। फसल का पैसा किसानों के खाते में पहुंच रहा है। विकास के साथ-साथ लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कल्याण करनाल के घरीडा में जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग की ओर से पेयजल के लिए बिजुई गई नई पाईप लाइन और 6 नलकूपों का उद्घाटन करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। इन पर 3 करोड़ 31 करोड़ रुपये की लागत आई है।

हाईकोर्ट बोला- राज्य ‘शोषक’ नहीं बन सकता, सेल्समैन से 81 महीने बिना वेतन काम पर कॉन्फेड पर 2 लाख जुर्माना

चंडीगढ़। करीब तीन दशक पुराने एक सेवा विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (कन्फेड) की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे कर्मचारी से 81 महीने तक काम लेकर वेतन न देने पर फटकार लगाई है। अदालत ने इसे न केवल प्रशासनिक उदासीनता बल्कि मानवीय गरिमा पर सीधा प्रहार माना। जस्टिस एचएस बराड़ की पीठ ने कन्फेड पर 2 लाख रुपये का हर्जाना लगाया और आदेश दिया कि कर्मचारी दूनी चंद को अक्टूबर 1989 से जुलाई 1996 तक का समस्त बकाया वेतन, सेवा लाभ तथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तीन महीने के भीतर भुगतान किया जाए।

दूनी चंद को वर्ष 1979 में सेल्समैन नियुक्त किया गया था। वर्ष 1983 में उनकी तैनाती मंडी डबवाली स्थित सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर में की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि

दूनी चंद को तीन दशक बाद मिला न्याय, वेतन और सेवा लाभ तीन माह में देने के आदेश



सितंबर 1989 से जुलाई 1996 तक उनसे लगातार कार्य लिया गया, लेकिन वेतन नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बिना किसी विधिसम्मत सेवा समाप्ति आदेश के उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। मामले में कन्फेड ने दलील दी कि दूनी चंद उसके नहीं बल्कि संबंधित स्टोर के कर्मचारी थे, इसलिए वेतन भुगतान की जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती। हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नियुक्ति कन्फेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई थी और पूरी सेवा अवधि में कर्मचारी पर

कन्फेड के सेवा नियम लागू रहे। अदालत ने रिकॉर्ड देखकर कहा कि याचिकाकर्ता 1991 से न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहा था। अप्रैल 1991 में ही वेतन जारी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। 1999 में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी, जिसे 2000 में इस आश्वासन पर निपटाया गया कि धन उपलब्ध होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद भी राहत न मिलने पर दूनी चंद को 2006 में फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा कि एक आम कर्मचारी को वर्षों तक बिना वेतन काम कराना न्यायिक चेतना को झकझोर देता है। अदालत ने टिप्पणी की कि जीवन, सम्मान और शोषण से मुक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है।

लॉ छात्रा को परीक्षा देने से रोकने पर हाईकोर्ट ने निजी विवि से जवाब मांगा

चंडीगढ़। बार पैर में फ्रैक्चर, महीनों के बेड रेस्ट और व्हीलचेयर के सहारे कॉलेज पहुंचकर पढ़ाई जारी रखने के बावजूद परीक्षा से रोके जाने का मामला अब अदालत पहुंच गया है। 19 वर्षीय लॉ छात्रा अक्षंबरी शर्मा का मामला छात्र अधिकार और मेडिकल आधार पर राहत से जुड़ा महत्वपूर्ण विवाद बन गया है। एससीकेएस ■ छात्रा के बाएं पैर में हो गया था फ्रैक्चर

एनएमआईएमएस विश्वविद्यालय की बीए एलएलबी (ऑनर्स) प्रथम वर्ष की छात्रा ने दूसरे सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से रोके जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। इस पर अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा और विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका के अनुसार, छात्रा ने पहले सेमेस्टर में 7.80 सीजीपीए हासिल किया था, लेकिन 31 जनवरी 2026 को बाएं पैर को मेटाटार्सल हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने 1 फरवरी से 20 मार्च तक बेड रेस्ट की सलाह दी, जिसके सभी मेडिकल दस्तावेज विश्वविद्यालय को सौंपे गए। इसके बावजूद छात्रा व्हीलचेयर के सहारे कॉलेज पहुंची और डिज-टम परीक्षा, विक्ज व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। बाद में उसे अर्टिडेंस कर्म होने का हवाला देकर परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया, जिसे उसने मनमानी कार्रवाई बताते हुए चुनौती दी है।

हरिभूमि ब्यूरो►► चंडीगढ़

प्रदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नीतियों और व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना बेहद आवश्यक है। साथ ही बदलती शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए नीतिगत और नियामक ढांचे को समय-समय पर अपडेट करना भी जरूरी है। मुख्य सचिव पंचकूला में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया के हरियाणा क्षेत्रीय अध्याय (आईटीपीआई-एचआरसी) द्वारा आयोजित राउंडटेबल चर्चा को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर



आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में लागू यह अधिनियम हरियाणा में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नगर नियोजन विशेषज्ञों और रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अधिनियम की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा

की। राउंडटेबल चर्चा को तीन सत्रों—लीडर्स राउंडटेबल, रियल एस्टेट उद्योग राउंडटेबल और प्लानर्स राउंडटेबल—में विभाजित किया गया। इसमें सतत शहरी विकास, मजबूत बुनियादी ढांचा और बदलती नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप कानून को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। लीडर्स राउंडटेबल में के. सरकार के औषधि विभाग के संयुक्त सचिव टीएल सत्यप्रकाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बदमाशों के फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोपी यूएई में धरा

हरियाणा पुलिस के वांछित भगोड़े आलोक कुमार उर्फ यशपाल सिंह को किया काबू

फर्जी पहचान पर बदमाशों को विदेश भागने में करता था मदद

हरिभूमि न्यूज़ ►► नई दिल्ली

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई में हरियाणा पुलिस के वांछित भगोड़े आलोक कुमार उर्फ यशपाल सिंह को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई 1 मई को पूरी की गई, जिसमें विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आलोक कुमार लंबे समय से हरियाणा में दर्ज एक गंभीर मामले में फरार चल रहा था। उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक

साजिश रचने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। जांच के अनुसार वह एक संगठित गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था, जो फर्जी दस्तावेजों और झूठी जानकारी के आधार पर लोगों के लिए भारतीय पासपोर्ट बनवाने का काम करता था। बताया गया है कि उसने कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को नकली पहचान और गलत पते के जरिए पासपोर्ट दिलाने में मदद की। इसके अलावा वह इन लोगों की विदेश यात्रा और आब्रजन से जुड़ी गतिविधियों का भी प्रबंधन करता था।

रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, भारत भेजने की दी मंजूरी



हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की एजेसियों ने आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भारत सरकार की ओर से औपचारिक रूप से उसे वापस भेजने का अनुरोध किया गया। सभी जरूरी काकांकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने आरोपी को भारत भेजने की मंजूरी दे दी।

खबर संक्षेप



मकान तोड़ते समय दीवार गिरने से व्यक्ति की दबकर मौत

रेवाड़ी। जाडरा गांव में शनिवार सुबह पुराना मकान तोड़ते समय अचानक दीवार गिरने से मलबे में दबकर मकान मालिक की मौत हो गई। रामपुरा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। जाडरा निवासी 52 वर्षीय भरत सिंह शनिवार को सुबह के समय पुराना मकान तोड़ रहा था। मकान तोड़ते समय एक दीवार अचानक गिर गई। भरत सिंह दीवार के मलबे में दब गया। इसी दौरान आसपास के ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने मलबे में दबे भरत सिंह को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी व दो बच्चे बताए जा रहे हैं। वह नया मकान बनाने के लिए पुराने मकान को ढहा रहा था। इसी दौरान अचानक दीवार गिरने से हादसा हो गया।

निवेश के नाम पर युवक से 37.5 लाख की ठगी

यमुनानगर। गांव दामला निवासी निपुण साइबर ठगी का शिकार हो गया। 11 अप्रैल को निपुण के व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से नरू महल कंपनी की वेबसाइट का लिंक भेजा गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद वह एक ग्रुप में जुड़ गया, जहां निवेश से जुड़े आकर्षक ऑफर दिए जा रहे थे। निपुण ने झांसे में आकर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच करीब 37.5 लाख रुपये जमा करवा दिए। बाद में जब उसे कोई मुनाफा नहीं मिला। उसने साइबर क्राइम थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

पत्नी की धमकियों से परेशान हो नहर में कूदा

पलवल। पलवल में एक युवक ने नहर में कूदकर सुसाइड कर लिया। औरंगाबाद गांव निवासी जिले सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा नर सिंह स्पेर्टस एकेडमी में काम करता था। पत्नी अंजलि से परेशान होकर उसने 1 मई को आगरा नहर में छलांग लगा दी। 2 मई को नर सिंह का शव बरामद हुआ। आरोप है कि शादी के बाद से ही अंजलि, सास महेंद्री और ससुर बच्चु सिंह नर सिंह पर जमीन अंजलि के नाम करने का दबाव बना रहे थे। वह उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। उसने दहेज का केस भी दर्ज करवाया था।

रहस्य

पहली बार कंकाल के पास डीस ऑन स्टैंड मिला

हरिभूमि न्यूज़ ►► नारनौद

ऐतिहासिक साइट राखीगढ़ी में चल रही खोदाई से हजारों साल पुरानी परतें हटाकर हड़प्पाकालीन सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। खोदाई में टीला 7 काफी अहम जाता है। एक बार फिर खोदाई में दो कंकाल निकल चुके हैं। संस्कार के समय रखे जाने बर्तन भी मिले हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बर्तनों के नीचे बड़ी संख्या में कंकाल मिल सकते हैं। जिनसे भी कंकाल सही हालत में मिलेंगे उनका डीएनए सैंपल लेकर लेब में भेजा जाएगा ताकि हड़प्पाकालीन सभ्यता



के बारे में दुनिया के सामने और तथ्य रखे जा सके कि यहां के लोग कैसे होते थे और ये यहां पर कब आकर बसे थे। राखी गढ़ी में टीले 7 पर हो रही खोदाई में लगातार चौंकाने वाले

अवशेष मिल रहे हैं। सबसे पहले दो कंकाल मिले। उनके स्त्रि की तरफ खाने का सामान रखने के लिए छोटे और बड़े बर्तन भी मिले हैं। पहली बार बर्तनों के साथ डीस ऑन स्टैंड

फरीदाबाद के रिहायशी क्षेत्र में फिर निकला अजगर



फरीदाबाद। हरकेश नगर क्षेत्र में नहर किनारे पांच दिन में दूसरी बार अजगर दिखाई दिया है। अजगर कई घंटों तक नहर किनारे ही बैठा रहा। इस दौरान उसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों ने वन्य एवं प्राणी विभाग को सूचित किया, लेकिन टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही अजगर धीरे-धीरे रेंगता हुआ नहर की ओर चला गया। इन्स्पेक्टर हंसराज ने बताया कि गर्मी के मौसम में जंगली जीव पानी और ठंडक की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं।

हाइड्रोजन ट्रेन को मरम्मत के लिए शकूर बस्ती भेजा

हाइड्रोजन प्लांट का लखनऊ से आरडीएसओ के महानिदेशक प्रभास दनसना ने निरीक्षण किया

हरिभूमि न्यूज़ ►► जींद

रेलवे जंक्शन पर हाइड्रोजन ट्रेन के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) व प्लांट में आरडब्ल्यूएस के निरीक्षण के बाद ट्रेन को मरम्मत के लिए दिल्ली शकूरबस्ती भेजा गया है। वहां से मरम्मत के बाद ट्रेन वापस जींद पहुंचेगी और इसके बाद ट्रेन के ट्रेक पर चलने की उम्मीद है। 28 अप्रैल

को सीसीआरएस जनक कुमार गर्ग अपने स्पेशल रेलवे कोच से हाइड्रोजन ट्रेन के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान प्लांट की तकनीकी व्यवस्थाओं, सुरक्षा मानकों और हाइड्रोजन ट्रेन संचालन से जुड़ी तैयारियों की बारीकी से जांच की थी। हाइड्रोजन प्लांट के निरीक्षण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई है, जिसके आने का इंतजार है। वहीं 30 अप्रैल को जंक्शन स्थित हाइड्रोजन प्लांट का लखनऊ से आरडीएसओ के महानिदेशक प्रभास दनसना ने निरीक्षण किया था। उन्होंने प्लांट की तकनीकी व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का बारीकी से जायजा



लिया। यहां हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति प्रणाली को परखा गया। टीम ने यह सुनिश्चित किया कि सभी उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और कहीं भी कोई तकनीकी खामी नहीं रहे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया

है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। अब दोनों अधिकारियों के निरीक्षण के बाद अब ट्रेन को मरम्मत के लिए दिल्ली शकूरबस्ती भेजा गया है। बता दें कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से सोनीपत के बीच चलाया जाना है।

ऐतिहासिक साइट राखीगढ़ी में एक बार फिर खुली इतिहास की परतें

राखीगढ़ी साइट की खोदाई में मिले दो कंकाल, रईस घराने से मिल रहा संबंध

हरिभूमि न्यूज़ ►► नारनौद

ऐतिहासिक साइट राखीगढ़ी में चल रही खोदाई से हजारों साल पुरानी परतें हटाकर हड़प्पाकालीन सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। खोदाई में टीला 7 काफी अहम जाता है। एक बार फिर खोदाई में दो कंकाल निकल चुके हैं। संस्कार के समय रखे जाने बर्तन भी मिले हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बर्तनों के नीचे बड़ी संख्या में कंकाल मिल सकते हैं। जिनसे भी कंकाल सही हालत में मिलेंगे उनका डीएनए सैंपल लेकर लेब में भेजा जाएगा ताकि हड़प्पाकालीन सभ्यता



के बारे में दुनिया के सामने और तथ्य रखे जा सके कि यहां के लोग कैसे होते थे और ये यहां पर कब आकर बसे थे। राखी गढ़ी में टीले 7 पर हो रही खोदाई में लगातार चौंकाने वाले

अवशेष मिल रहे हैं। सबसे पहले दो कंकाल मिले। उनके स्त्रि की तरफ खाने का सामान रखने के लिए छोटे और बड़े बर्तन भी मिले हैं। पहली बार बर्तनों के साथ डीस ऑन स्टैंड

भी मिला है। जिस पर वे लोग खाना रखकर खाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा कि ये कंकाल किसी बड़े घराने के आदमी के हो सकते हैं। जिनके घर में खाना खाने के लिए डीस ऑन स्टैंड का प्रयोग होता होगा।

अभी तक जितने भी कंकाल मिले हैं। उनके साथ में सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही रखे मिले हैं। कंकाल के साथ में अब तक कच्ची ईंटें रखी होने के अवशेष मिले हैं। पहली बार पक्की ईंटें भी कंकाल के पास में मिली हैं। इसको लेकर शोधकर्ता बड़ी बारीकी से खोदाई के कार्य में जुटे हुए हैं।

अगोहा में मिली मुहरें अगोहा। अगोहा के ऐतिहासिक टीले की खोदाई में मिली मुहरों पर संस्कृत व बाहमी लिपि में लिखे संदेश मिले हैं। यह मुहरें पांचवीं-छठी शताब्दी में विष्णु गुप्त के शासनकाल की मानी जा रही हैं। इनकी वास्तविक आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग की जाएगी। टीले पर दो महीने से अधिक समय से चल रहा खोदाई कार्य गर्मी के कारण फिलहाल बंद कर दिया है। नवंबर में फिर खोदाई शुरू होगी।

विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी

हरिभूमि न्यूज़ ►► रतिया

रतिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर ली है। शनिवार को हिसार के उकलाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नापा ने विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की उपस्थिति में पार्टी का पटका पहना। इस अवसर पर बड़ौली ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि लक्ष्मण नापा के आने से न केवल रतिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पार्टी को मजबूती



लक्ष्मण नापा को भाजपा ज्वाइन कराते प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली।

मिलेगी। पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी की जनकल्याणकारी नीतियों से प्रभावित हैं और इन्हीं नीतियों के चलते वह दोबारा से भाजपा में आए हैं। नापा ने अपनी वापसी को 'घर वापसी' करार दिया।

2019 में जीते थे चुनाव

2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लक्ष्मण नापा पर भरोसा जताया था। उन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज की और रतिया से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने रतिया सीट से लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया था। पार्टी ने उनकी जगह पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा। टिकट कटने से नाराज होकर नापा ने बगावती रुख अपनाया और चुनाव से ठीक पहले भाजपा को अलविदा कह दिया था। भाजपा छोड़ने के बाद लक्ष्मण नापा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थामा था। कुछ महीनों के 'वनराज' के बाद नापा ने अब फिर से कर्मल थामा है।

करनाल में मेयर का फर्जी पीए बनकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ ►► करनाल

जिला पुलिस करनाल के थाना सिविल लाइन की टीम ने मेयर का फर्जी पीए बनकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी ओम प्रकाश उर्फ प्रदीप पुत्र लाजपत राय, मूल निवासी समाना मंडी जिला पटियाला (पंजाब) व हाल निवासी कर्ण विहार, करनाल को काबू किया। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार आरोपी खुद को मेयर का पीए बताकर लोगों को



झांसे में लेता था और उनसे पैसे लेकर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अंबाला में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ में एक आम आदमी की गई जान

बाइक सवार को पुलिस कर्मी समझकर गोतस्कर ने गोली मारकर की हत्या

हरिभूमि न्यूज़ ►► अंबाला

शुक्रवार देर रात पिकअप सवार गो-तस्करों ने एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर पीछे बैठा उसका दोस्त बाल-बाल बच गया। गो-तस्करों के पीछे पुलिस की टीमें लगी हुई थीं। आरोपी पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर भाग रहे थे। कुछ दूरी पर बाइक सवार युवकों को पुलिसकर्मी समझकर तस्करों ने उन पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक के माथे पर गोली लग गई। इसके बाद तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजोखरा थाना क्षेत्र के टुंडला के पास गो-तस्कर घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तस्करों को घेरने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गाड़ी के शोशे पर गोली भी लगी। इसी दौरान गरनाला के गुप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी (25) अपने दोस्त नक्षत्र सिंह के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। दोनों एक कैटीन में काम करते



अंबाला। पीड़ित परिवार के परिजनों से बातचीत करते मंत्री अनिल विज।

अस्पताल में परिजनों से मिले मंत्री अनिल विज शनिवार सुबह जब वारदात की सूचना कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लगी तो वह सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने गुरप्रीत के परिजनों को दौलत बंधाया और गो तस्करों को जल्दी गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अंबाला के एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार भी ऐसे गो-तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा।

थे। जब वे तोपखाना रोड पर टुंडला मोड़ के पास पहुंचे तो सामने पिकअप में वही गो-तस्कर आ रहे थे। उनका पुलिस पीछा कर रही थी। रात के अंधेरे में हेलमेट पहने दोनों युवकों को देखकर तस्करों को लगा कि सामने पुलिस की नाकाबंदी है। दोनों युवक पुलिसकर्मी हैं। खुद को धिक्ता देख उन्होंने देसी कट्टे से बाइक सवारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक गोली सीधे गुरप्रीत सिंह के माथे पर लगी, जिससे वह लहलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा।

बाद में उसकी मौत हो गई। इस हमले में नक्षत्र सिंह बाल-बाल बच गया। कुछ दूरी पर अपनी पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पिकअप में एक बैल और एक गाय लदी हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सख्त अभियान चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तस्करों को पकड़ लिया जाएगा।

पंजाब पुलिस की रतिया में रेड

भगोड़े को पंजाब पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले गई भीड़, दोनों आरोपी फरार

हरिभूमि न्यूज़ ►► रतिया

गांव बुर्ज में शनिवार को पंजाब पुलिस की रेड के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब भगोड़े आरोपियों को पकड़ने पहुंची टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। पुलिस के कब्जे में आया आरोपी भी भीड़ छुड़ाकर ले गई और दोनों आरोपी फरार हो गए। वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में भगोड़े घोषित किए गए रणजीत सिंह और साधु सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब के बरेठा थाना क्षेत्र से पुलिस टीम गांव बुर्ज पहुंची थी। यह टीम पीओ स्टाफ मानसा के सहायक उपनिरीक्षक सुखदेव सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई कर रही थी। स्थानीय सदर थाना के दो पुलिसकर्मी भी साथ मौजूद थे। पुलिस ने गांव में दबिश देते हुए रणजीत सिंह को काबू कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी साधु सिंह फरार हो गया। पुलिस जब पकड़े गए आरोपी को लेकर वापस लौट रही थी, तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की गिरफ्त से रणजीत सिंह को भी छुड़ा लिया और वह मौके से फरार हो गया। सदर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि दोनों भगोड़े आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। हालांकि उन्होंने पुलिस टीम के साथ हाथापाई की घटना से इनकार किया और कहा कि पंजाब पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई शिकायत नहीं दी गई है। गौरतलब है कि जाखल के गांव भिमोद निवासी रणजीत सिंह और साधु सिंह के खिलाफ 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। जमानत पर आने के बाद दोनों अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

रतिया के पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा ने कांग्रेस छोड़ थामा भाजपा का दामन

विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी

हरिभूमि न्यूज़ ►► रतिया

रतिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर ली है। शनिवार को हिसार के उकलाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नापा ने विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की उपस्थिति में पार्टी का पटका पहना। इस अवसर पर बड़ौली ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि लक्ष्मण नापा के आने से न केवल रतिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पार्टी को मजबूती



लक्ष्मण नापा को भाजपा ज्वाइन कराते प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली।

मिलेगी। पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी की जनकल्याणकारी नीतियों से प्रभावित हैं और इन्हीं नीतियों के चलते वह दोबारा से भाजपा में आए हैं। नापा ने अपनी वापसी को 'घर वापसी' करार दिया।

टीएमसी को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका कर दी खारिज

एजेसी ► नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा।

सर्कुलर का दिया गया हवाला

टीएमसी के अनुसार इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के वकील के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा।



कर्मचारियों की नियुक्ति का मानला

यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। टीएमसी इसी का विरोध कर रही है। उसका मानना है इसमें राज्य कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाए।

अधिकारी कहाँ का इससे फर्क नहीं पड़ता

जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना में हर राजनीतिक दल के एजेंट मौजूद रहेंगे। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है।

नियमों में विकल्प मौजूद

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी।

सिबबल ने नियुक्ति की स्पष्टता पर उठाए सवाल



टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिबबल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए। सिबबल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे। टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जानबूझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है।

फैसले पर बोली भाजपा

चुनाव प्रक्रिया पर शक करने वालों को मिला जवाब
बंगाल में मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के चुनाव आयोग के आदेश में दरखल से सुप्रीम कोर्ट के इनकार ने चुनाव प्रक्रिया पर शक पैदा करने की कोशिशों के खिलाफ एक 'स्पष्ट संदेश' दिया है। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने यह बात कही। शीर्ष कोर्ट ने कहा टीएमसी की उस याचिका पर किसी और आदेश की जरूरत नहीं है, जिसमें उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मियों की तैनाती संबंधी आदेश को सही माना था।

खबर संक्षेप

बम धमाके में मारे गए बच्चों के शव परिवार को सौंपे

ईफाल। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में पिछले महीने हुए धमाके में मारे गए दो बच्चों के शव शनिवार को उनके परिजनों को सौंप दिए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि परिवार ने दोषियों को यथा शीघ्र दंडित करने की मांग करते हुए शवों को लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से पांच वर्षीय लड़के और उसकी छह महीने की बहन की लाश गत 25 दिन मुर्दाघर में रखनी पड़ी।

रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब में पटियाला के शंभू क्षेत्र में फ्रेंट कारिडोर रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के अनुसार, गुरजिंदर सिंह उर्फ बाबा बियंत को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, पटियाला पुलिस और पटानकोट की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

राशिफल

	आशा-निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। बातचीत में सन्तुलन बनाये रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें।
	धैर्यशीलता बनाये रखने का प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव की सम्भावना बन रही है। परिश्रम अधिक रहेगा।
	मन प्रसन्न रहेगा। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं।
	आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परन्तु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे।
	नौकरी के लिए साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी, परन्तु किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी।
	शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। शैक्षिक कार्यों के लिए भी विदेश जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं।
	जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का सानिध्य मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
	मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा, परन्तु पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। खर्च बढ़ेंगे।
	मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु आत्मसंयत रही रहे। कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंताओं पर नियंत्रण बनाकर रखें।
	शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी मिल सकती है। आय में वृद्धि भी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें।
	भागदौड़ अधिक रहेगी। परन्तु किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफलता के भी योग हैं।
	मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। भाग-दौड़ भी अधिक रहेगी।

चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार, चाहे अधिकारी केंद्र के हों या राज्य सरकार के फर्क नहीं पड़ता, नए आदेश की जरूरत नहीं

वोटों की गिनती के लिए स्टाफ को तैनात करने के खिलाफ सुनवाई

राहुल गांधी मानहानि मामले में अदालत ने ‘वॉइस सैपल’ की अर्जी खारिज की

सुलतानपुर (भाषा)। सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत ने शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में उनकी आज्ञा का नमूना (वॉइस सैपल) लेने की याचिका खारिज कर दी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायित्व करेंगे। पांडेय ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन देकर अनुरोध किया था कि केस डायरी में मौजूद सीडी से मिलान के लिए राहुल गांधी का 'वॉइस सैपल' लिया जाए और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाए। इस पर पिछली सुनवाई 22 अप्रैल को हुई थी। शनिवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला और वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मई तय की है। यह मानहानि का मुकदमा माजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

COURT NOTICE IN THE COURT OF Sh. Narendar Singh Additional District and Sessions Judge, Sonapat Equites Small finance Bank Ltd through Narinder Singh Vs. Surender Singh CNR No. HRS001-009772-2025 Next Date : 06.07.2026	PUBLICATION ISSUED TO :- Respondent No. 3. VIJAY SAINI BRANCH MANAGER SHRI RAM CITY UNION FINANCE LTD AT FIRST FLOOR 213 R, ATLAS ROAD OPPOSITE CHHABRA NURSING HOME SONEPAT Respondent No. 4- Devender Sharma, Branch Manager, Shriram City Union Finance Ltd. At Shriram City Union Finance Ltd. Rouse Tower, Upper Ghar Market, Near Indus Bank, Civil Road, Rohtak. In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 06-07-2026 at 10.00 a.m. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Sonapat Sd/- Additional District and Sessions Judge, Sonipat
---	---

निविदा सूचना

जिला सोनीपत में पावर ग्रिड द्वारा निम्नलिखित 16 गांवों भटना जाफराबाद, किलोहडद, शहजदपुर, बड़वासनी, महलाना, ककरोई, रोहट, हरसाना कलां, नसीरपुर, मौआपुर, बिहरोली, अब्बासपुर, नाहरा, हवालपुर, झीझोली एवं कान्लपुर से होकर निकाली जा रही विद्युत लाइन के मूल्यानुसार कार्य हेतु योग्य एजेंसियों / बैल्यूयर्स से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
निविदा में भाग लेने हेतु निम्न शर्तें अनिवार्य होंगी: बैल्यूयर का पंजीकरण IBB (Insolvency and Bankruptcy Board of India) में होना आवश्यक है।
1. संबंधित कार्य में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. निविदा पत्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 07 मई 2026 सायं 04:00 बजे तक निर्धारित की गई है। निविदाएं कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत में जमा करवाई जाएंगी।
नोट अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत में दूरभाष नं० 0130-2222700 पर संपर्क किया जा सकता है।
अतिरिक्त उपायुक्त,
सोनीपत (हरियाणा)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त **मनीष उर्फ बंटी** पुत्र ओम प्रकाश निवासी: वीपीओ असाउदा टोडरान, जिला झज्जर, हरियाणा ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 321/2022 धारा 25 शस्त्र अधिनियम धाना अमन विहार, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **मनीष उर्फ बंटी** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **मनीष उर्फ बंटी** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा **धारा 82 Cr.P.C.** की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 321/2022 धारा 25 शस्त्र अधिनियम धाना अमन विहार, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **मनीष उर्फ बंटी** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए **30.06.2026** को हाजिर हो।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, उत्तर-पश्चिम न्यायालय संख्या 109, प्रथम तल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली।

DP/5746/RD/2026

पुलिस को चलानी पड़ी लाटियां

दक्षिण 24 परगना जिले के 15 केंद्रों पर री-पोल

पुनर्गतदान के बीच भारी सुरक्षा बल तैनात



भिड़ गए भाजपा-टीएमसी कार्यकर्ता

बंगाल में फाल्ता में हिंसा की खबरें हैं। यहां टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसके बाद लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाटियां भांजनी पड़ी। फाल्ता सीट पर दोबारा वोटिंग नहीं करवाई जा रही है। फाल्ता में भाजपा समर्थकों का कहना है कि उन्हें टीएमसी के लोगों से लगातार धमकियां मिल रही हैं और वोटों की गिनती के दौरान हिंसा की आशंका है। इसी को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे थे। टीएमसी के कार्यकर्ता भी निकल गए और इस प्रदर्शन का विरोध करने लगे। इस पर दोनों में हाथापाई हो गई।

शाहनवाज-नकवी ने साधा निशाना

हार तय देख बहाने बना रही टीएमसी



नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि टीएमसी चुनाव पहले ही हार चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब झुमा कर रही है। कभी स्ट्रॉन रूम में घुसने की कोशिश करती है, तो कभी अदालत का रुख करती है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बंगाल चुनाव में एक पैटर्न दिख रहा है। हारने पर शिकायत और जीतने पर मुद्दों को भुला देना।

सेंटर फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में यह तकनीक देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम दिल्ली के एम्स में शुरू हुआ

एजेसी ► नई दिल्ली

देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाते हुए भारत का पहला पोर्टेबल बेंडसाइड एमआरआई सिस्टम शुरू किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए तेज और सुरक्षित ब्रेन इमेजिंग को संभव बनाएगी। इस पोर्टेबल एमआरआई मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सीधे मरीज के बेड तक ले जाया जा सकता है। पारंपरिक एमआरआई स्कैन में मरीज को विशेष कक्ष तक ले जाना पड़ता है, जबकि नई प्रणाली आईसीयू, इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी वार्ड में ही स्कैनिंग की सुविधा देती है। इससे गंभीर मरीजों को ट्रांसफर करने का जोखिम काफी कम हो जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पहल देशभर में ब्रेन इमेजिंग की पहुंच बढ़ाने के साथ पॉइंट-ऑफ-केयर न्यूरोडायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में शोध को नई दिशा देगी। इसे भारत के स्वास्थ्य तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में अहम उपलब्धि माना जा रहा है। एम्स के सेंटर फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में इस तकनीक का उपयोग शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों की टीम डॉ. शैलेश गायकवाड़ के नेतृत्व में मरीजों की जांच कर रही है। अल्ट्रा-लो-फील्ड तकनीक पर आधारित यह पोर्टेबल एमआरआई आपात स्थितियों में तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगा, खासकर तब जब पारंपरिक इमेजिंग कराना कठिन या जोखिम भरा हो।

एक भी वोट के हेरफेर की गुंजाइश नहीं

इसी ने तैनात किए 242 नए ऑब्जर्वर



बंगाल में वोटों की गिनती 4 मई को होनी है और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसी ने पूरी तैयारी कर ली है। 242 नए ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इनमें 165 मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक शामिल हैं। आयोग ने अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने तैनात किया है कि मतगणना सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी माहौल में हो।

पाकिस्तानी महिला से निकाह किया तो बीवी ने 4 बच्चों को ईट से कुचलकर मार डाला



एजेसी ► आबेडकरणगर

अकबरपुर के मीरानपुर मोहल्ले में शनिवार की दोपहर तीन बजे एक घर में बिस्तर पर चार बच्चों के खून से लथपथ शव मिले। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और बच्चों की मां घर से गायब थी। बताया जा रहा है कि महकूआ निवासी नियाज की पत्नी अपने पुत्र शफीक, सउद, उमर व पुत्री

बयान के साथ मीरानपुर में रहती थी। नियाज सऊदी अरब में पिछले कई वर्षों से नौकरी करता है और उसने वहीं पर किसी पाकिस्तानी महिला से निकाह भी कर लिया। इसी बात को लेकर महिला तनावग्रस्त रहती थी और उसी ने ईट से कुचकर पहले बच्चों की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद बालकनी से कूद कर भाग गई।

30.मन मोहने वाला-5 ऊपर से नीचे

- आरामदायी-5
- एक अनमोल रत्न, दुलारा-2
- समा शुल्क-3
- अभिव्यक्ति-3
- बचत, जोड़-2
- वहम-2
- स्वामी-3
- प्रवेश-3
- धरोहर, थाती-4
- तरंग, हिलोर-3
- निरंकुश, मुंहजोर-4
- किनारा, तट
- कामधेनु, सुगंध-3
- नुकसानदेह-5
- दुनिया, जग-3
- कहासुनी-4
- चयन-3

24.चट्टान, शिला (अंग्रेजी-2)

- इश्वर, भगवान-2
- प्रेम, लगन-2

शब्द पहली - 6213 का हल

ब	व	न	वा	ज	अ	स	मा	न
न	दी	र	ल	ब	बा	द	र	ज
व	ज	म	ज	म	ब	री	क	
जी	म	ना	ह	ठ	ता	क	त	
ब	चा	जे	ल	पे	ता			
न	ग	र	से	ठ	फ	को	र	ना
री	ना	स	ना	रो	म			
सु	ब	ह	दा	म	ब्रा	री	क	
र	क	श	अ	न	का	र	र	
ता	प	प	दा	म	क	ण		
ल	थ	प	थ	र	च	ना	का	र

खबर संक्षेप

अजमेर दरगाह में 'शिव मंदिर', फैसला सुरक्षित



अजमेर। दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर जिला कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। दावे को लेकर याचिका पर शनिवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षों ने अपने-अपने दावे के समर्थन में कानूनी तर्क और दस्तावेज पेश किए। हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना द्वारा याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

कर्नाटक में ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया रविवार को कर्नाटक के डोड्डाबल्लापुर में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से बेल्लारी में एक और 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। श्रमिकों और परिवारों को सुविधाएं मिलेंगी।

निदा खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार

नासिक। नासिक की एक अदालत ने शनिवार को टीपीएस की नासिक इकाई में कथित यौन उत्पीड़न और जबर्न धर्म परिवर्तन से संबंधित मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने निदा खान से हिरासत में पृछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया। लोक अभियोजक अजय मिसर ने पत्रकारों से कहा, रयह एक गंभीर अपराध है। निदा खान मुख्य आरोपियों में से एक है, इसलिए उससे हिरासत में पृछताछ आवश्यक है।

राजकोट के आजी बांध में नहाने गए 6 युवक डूबे



राजकोट । गुजरात के राजकोट से दुःखद खबर सामने आई है, जहां आजी बांध के पास स्थित मुगल माताजी मंदिर के दर्शन के लिए आए एक ही परिवार के चार सदस्य गहरे पानी में डूब गए। इनमें से पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि पानी में लापता एक युवक की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजकोट शहर के घंघीवाड़ में रहने वाले और रिक्शा चलाकर जीविका कमाने वाले भरत जादव (42) अपने दो बेटों धवल और रोहित और अपनी साली के बेटे ध्रुव को रिक्शा में बिठाकर अजी बांध के पास मुगल माताजी से मिलने गए।

सफलता

देश को जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलें मिलेंगी
ब्रह्मोस मिसाइलों से दोगुनी होगी रफ्तार

एजेंसी ►► नई दिल्ली

यूनिआ भर में युद्धों की बदलती रणनीति को देखते हुए भारत ने भी अपनी तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही देश भारत अत्याधुनिक 'हाइपरसोनिक' मिसाइल तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। डीआरडीओ प्रमुख समीर बी. कामत ने एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश जल्द 'हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल' और 'हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल' से लैस होगा। इनकी रफ्तार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से दोगुनी होगी। इसकी खासियतों की वजह से दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। डीआरडीओ प्रमुख के अनुसार, ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जल्द संभव है।



खास बातें

- कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा
- डीआरडीओ प्रमुख कामत ने दी जानकारी
- ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जल्द संभव
- अग्नि-6 पर हरी झंडी मिलते काम होगा शुरू

यूपीडा ने स्विट्जरलैंड की ईटीएच ज्यूरिख और आरटीडीटी लैबोरेट्रीज एजी के साथ की साझेदारी

भाषा ►► लखनऊ

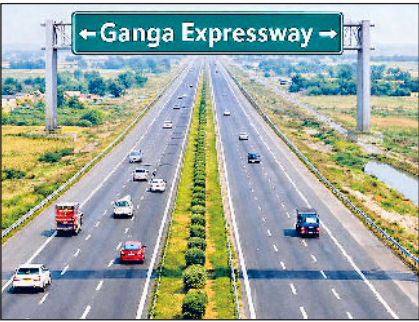
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण अब पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर तकनीक आधारित निगरानी और प्रबंधन की ओर बढ़ रहा है। शनिवार को आधिकारिक जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कृत्रिम मेधा (एआई) और 'स्विस सेंसर' तकनीक के जरिए सड़क निर्माण को 'डेटा-आधारित' और 'समय पर निगरानी' आधारित बना रही है। गंगा एक्सप्रेसवे में भी इस तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसका लोकार्पण हाल में पीएम मोदी ने किया था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने स्विट्जरलैंड की 'ईटीएच ज्यूरिख' और 'आरटीडीटी लैबोरेट्रीज एजी' के साथ साझेदारी की है। इस तकनीक से निर्माण के दौरान ही सड़क की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है।

एआई और स्विस तकनीक से लैस है उग्र का गंगा एक्सप्रेसवे, मिलेगा रीयल टाइम डेटा

विशेष वाहन में सात 'एक्सेलेरोमीटर सेंसर' लगाए गए हैं। यह वाहन एक्सप्रेसवे की हर लेन पर चलकर सतह की एकरूपता, ऊंचाई में उतार-चढ़ाव और कंपन का डेटा जुटाता है। सेंसर आंकड़ों को एआई सॉफ्टवेयर से 'प्रोसेस' कर सड़क की गुणवत्ता को 'ज्ञानदार', 'अच्छा' व 'खराब' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इससे खामियों की पहचान निर्माण के दौरान ही हो जाती है।

सड़क की 'रीयल कंडीशन' का वैज्ञानिक आकलन

स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, सुरक्षा पर सीधा असर



एआई-सक्षम कैमरे लगाए जा रहे

यूपीडा अधिकारियों के मुताबिक, पहले गुणवत्ता का आकलन निर्माण पूरा होने के बाद होता था, जिससे सुधार में समय और लागत बढ़ती थी। नई प्रणाली से खामियों को उसी समय दुरुस्त किया जा सकेगा। निर्माण के बाद संवाहन चरण में एआई-सक्षम कैमरे लगाए जा रहें हैं। ये कैमरे तेज रफ्तार, गलत लेन में चलने जैसे यातायात नियम उल्लंघनों को स्वतः चिन्हित करेंगे। इससे नियमों का क्रियान्वयन मजबूत होने और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से एक्सप्रेसवे केवल 'कनेक्टिविटी' का माध्यम न रहकर डेटा, तकनीक और प्रबंधन के समन्वय से संचालित 'इंटीलिजेंट नेटवर्क' के रूप में विकसित हो रहे हैं।

मौसम विभाग ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की

बदला मौसम, 9 राज्यों में तेज आंधी और बारिश, कई जगह ओले भी गिरे

एजेंसी ►► नई दिल्ली

भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत मिली। 9 राज्यों में आंधी-बारिश आई। कई जगह ओले भी गिरे। उत्तर प्रदेश के दोपहर एक बजे के बाद ललितपुर और झांसी में धूलभरी आंधी चली। कुछ इलाकों में बूंदबांंदी हुई। झांसी मैडिकल कॉलेज में एक बड़ा पेड़ स्कूटी और कार पर गिर गया। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और बालाघाट में बारिश हुई। कई जगह आंधी भी आई। मप्र के 21 जिलों में बारिश होने की चेतावनी जारी की है। रायसेन में तेज आंधी से गोदाम की छत उड़ गई, किसानों का गेहूं भीग गया। बालाघाट और सीहोर में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कश्मीर की चिनाब घाटी में लैंडस्लाइड के कारण डोडा-किश्तवाड़ रोड पूरी तरह बंद हो गई है। मलबे को हटाने के लिए मशीनें व कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं।

शिमला में बदला मौसम
अंधेरा छाया, रेलो अलर्ट

पूर्वोत्तर राज्यों में 5 दिनों तक गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। बारिश भी होगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में दिनभर की धूप के बाद शाम के वक्त अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई है। शिमला के साथ साथ ठिबो, कुफरी, फागू और सोलन के कई क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। मौसम बदलने के बाद शाम 5.30 बजे ही शिमला में अचानक अंधेरा सा छा गया।

हिमाचल प्रदेश में मौसम के बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश होने का पूर्वानुमान है। चोटियों पर बर्फबारी की भी संभावना है।



उत्तर प्रदेश में कई जगह गिरे पेड़, बिजली रही गुल



►► मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश और ओलों का अलर्ट

►► कश्मीर में लैंडस्लाइड, डोडा किश्तवाड़ रोड बंद, जाम

►► मई माह में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने मई में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने और कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। साथ ही अलग-अलग इलाकों में टेम्परेचर मिला-जुला रहेगा। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। असम, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ अलग-अलग स्थानों पर (7-20 सेमी) बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान आया। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है।

वार्ता के दौरान कहा कि हालांकि कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान और लू की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन यह पूरे देश में समान रूप से नहीं होगा। समय पर तैयारी और समय-समय पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी सलाह का पालन करके इन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।



केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले

मई की गर्मी से घबराने की जरूरत नहीं, सावधानी व तैयारी से स्थिति काबू में

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को लोगों को आश्वासन करते हुए कहा कि मई में संभावित गर्मी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंह ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान को सही ढंग से समझकर और दैनिक जीवन में सरल सावधानियां

अपनाकर किसी भी अफ्रिय घटना से बचा जा सकता है। उन्होंने अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस

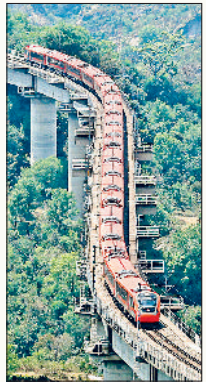


जम्मू में जांच के बाद रवाना हुई वंदेभारत

जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू

एजेंसी ►► जम्मू

जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच शनिवार को से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह छः बजकर 20 मिनट पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन रवाना करके किया था। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया था। पहली नियमित सेवा में यात्रा कर रहे यात्रियों ने खुशी व्यक्त की और इस हाई-स्पीड ट्रेन सेवा को शुरू करने के लिए मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी पहल बताया। यात्रियों ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए इससे मिलने वाली सुगमता और बेहतर संपर्क पर बल दिया। वंदे भारत से यात्रा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है।



धर्मांतरण के विरोध पर टूट पड़ी भीड़
घेरकर लाठी और धारदार हथियारों से किए वार,4 घायल, 115 पर केस

एक की हालत गंभीर
गुजरात के दाहोद रेफर 15 नामजद पर केस दर्ज, चार गिरफ्तार

एजेंसी ►► बांसवाड़ा



पुलिस तक पहुंचा मामला

कुशलगढ़ निवासी रवि भाभोर ने जोसफ उर्फ जयसिंह सहित अन्य के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्हें सूचना मिली थी कि गांव के पास स्थित डैम क्षेत्र में प्रतिबंधित मवेशी (गाय) को नुकसान पहुंचाने के साथ ही धर्मांतरण जैसी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इस सूचना पर वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया और अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से वार किए।

हाईकोर्ट ने बैंक को दिया आदेश
कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये का भुगतान करें

एजेंसी ►► देहरादून

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें बैंक को एक पुलिस कांस्टेबल की विधवा को बीमा लाभ के रूप में 25 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

चौफ जरिस्टस मनोज कुमार गुप्ता और जरिस्टस सुभाष उपाध्याय की बेंच सिंगल जज के फैसले को चुनौती देने वाली बैंक की याचिका पर यह कहा सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने 30 अप्रैल को कहा था कि अपीलकर्ता बैंक इस बात से इनकार नहीं करता कि प्रतिवादी के पति का बैंक में वेतनभोगी खाता था।

वेतन जमा करने में कोई भूल नहीं थी



उच्च न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया कि वेतन जमा करने में कोई भूल नहीं हुई थी। हालांकि, दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार यह है कि प्रतिवादी के पति का नाम पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई कर्मचारियों की सूची में शामिल नहीं था। इसी पर सबकी निगाह टिकी थी।

कुर्क संपत्तियों

का मूल्य 81,000 करोड़ से अधिक रहा

भाषा ►► नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान धनशोधन मामलों में की गई गिरफ्तारियों में लगभग 27 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन इस अवधि के दौरान कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 81,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़े से मिली। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रावधानों के तहत केंद्रीय एजेंसी द्वारा तलाशी या छापेमारी की संख्या 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग दोगुनी होकर 2,892 हो गई।



अप्रत्यक्ष से प्राप्त आय की परिभाषा, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती तथा संपत्ति कुर्क करने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पीएमएलए के तहत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। प्रावधानों के कारण जमानत प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन हो जाता है क्योंकि अदालत का यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अन्य अपराध करने की आशंका नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष में, ईडी ने घोषाघड़ी के पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियां वापस लौटाने के अपने निर्धारित लक्ष्य को दोगुने से पार कर लिया, क्योंकि उसने उक्त अवधि के दौरान 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां वापस कीं। एजेंसी ने 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस लौटाने का लक्ष्य रखा था।

वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े का अध्ययन किया

एजेंसी द्वारा उसकी वार्षिक रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2025-26) में उपलब्ध कराए गए आंकड़े का अध्ययन किया और पाया कि ईडी ने उल्लेखित वित्त वर्ष में 156 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2024-25 में यह संख्या 214 थी, यानी लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट। 2023-24 में यह संख्या 272 थी। ईडी ने बताया कि गिरफ्तारियों में कमी का कारण यह है कि वह "अधिक लक्षित और सक्षम-आधारित जांच" कर रही है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026 में उसके द्वारा की गई संपत्तियों की "अप्रत्यक्ष की संसरे अधिक" अस्थायी कुर्की के बारे में कहा कि यह 712 आदेशों के तहत 81,422 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और यह वृद्धि पिछले साल के मुकाबले 171 प्रतिशत अधिक है।

सेंसर से प्राप्त डेटा से तय होगी सड़क की गुणवत्ता

सेंसर से प्राप्त आंकड़ों को एआई सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेस कर सड़क की गुणवत्ता को 'एक्सीलेंट', 'गुड' और 'पूअर' जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इससे न केवल गुणवत्ता का पर्युनिट मूल्यांकन संभव होता है, बल्कि निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होती है। खास बात यह है कि एआई आधारित यह सिस्टम सड़क की छोटी-से-छोटी खामों को भी पहचान लेता है, जिससे समय रहते सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्परकार अब निर्माण के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी समेकन पर पर ध्यान दे रही है।

भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष



लेह। लद्दाख के लेह में 'तथागत के पवित्र अवशेषों की पवित्र प्रदर्शनी' के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित किया गया।

बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए श्रद्धांजलि प्रकट करने का अवसर: मोदी

नई दिल्ली (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लेह में 'तथागत के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी' के उद्घाटन की शनिवार को सराहना की और कहा कि लद्दाख के लोगों के लिए यह श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आने दो दिवसीय लद्दाख दौरे के दौरान लेह में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा से जुड़े समारोह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट किया।

812 आरोपपत्र दाखिल किए, जो एक 'रिकॉर्ड'

○वित्त वर्ष 2026 में पिछले वर्ष के 1,491 छापों की तुलना में दोगुनी से अधिक बढ़कर 2,892 हो गई।
○ईडी ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान सफलतापूर्वक 812 आरोपपत्र दाखिल किए, जो एक 'रिकॉर्ड' है, पिछले वर्ष अदालतों में केवल 457 आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।
○पीएमएलए जांच शुरू करने के लिए दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में 39 प्रतिशत बढ़कर 1,080 मामले हो गई
○जबकि वित्त वर्ष 2025 में केवल 775 मामले दर्ज किए गए थे। एजेंसी ने पिछले वित्त वर्ष में 32,678 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कीं, जबकि वित्त वर्ष 2025 में धोखाधड़ी के पीड़ितों ने 15,263 करोड़ रुपये की संपत्तियां सौंपी गईं।
○ईडी निदेशक राहुल नवीन ने वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस दिलाने का लक्ष्य रखा था।

चुनाव ख़त्म होते ही देश की राजनीतिक घड़कनें तेज हो जाती हैं और इसी के साथ एगिजट पोल का दौर शुरू होता है। टीवी स्क्रीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म व सोशल मीडिया पर आंकड़ों की बाढ़ आ जाती है, जहां हर एजेंसी अपने-अपने अनुमान पेश करती है। ये आंकड़े न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक संकेत होते हैं, बल्कि आम मतदाता के लिए भी जिज्ञासा और बहस का विषय बन जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एगिजट पोल वास्तव में जनादेश का सटीक प्रतिबिंब हैं या महज एक अनुमान, जो कई बार हकीकत से काफी दूर होता है? पिछले कुछ वर्षों में एगिजट पोल की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कई चुनावों में इनके नतीजे वास्तविक परिणामों से मेल नहीं खा पाए, जिससे जनता के बीच अविश्वास की भावना बढ़ी है। खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, जहां सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक जटिलताएं अधिक हैं, एगिजट पोल अक्सर वास्तविक जनमत को पकड़ने में असफल रहे हैं। दरअसल, भारत जैसे विशाल देश में कुछ हजार लोगों के सैंपल के आधार पर करोड़ों मतदाताओं के रुझान का सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी एगिजट पोल पूरी तरह निरर्थक नहीं हैं। वे चुनावी प्रवृत्तियों, मतदाता मनोविज्ञान और संभावित राजनीतिक दिशा का एक प्रारंभिक संकेत जरूर देते हैं। *इन्हीं हालातों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

केवल प्रतिक्रियाओं के अनुसार मत न बनाएं



एगिजट पोल

अवधेश कुमार

आपिनियन पोल और एगिजट पोल पर राजनीतिक दलों व कुछ टिप्पणीकारों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों से उनकी विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा है। ऐसा माहौल बना हुआ है मानो सारे एगिजट पोल आज तक गलत ही साबित हुए हैं। सच ऐसा नहीं है। एगिजट पोल का यह अर्थ नहीं कि वे जितनी सीटें बताते हैं वास्तव में उतने ही आ सकते हैं या आने चाहिए। एगिजट पोल से हमें चुनाव परिणाम का भावी ट्रेंड यानी प्रवृत्ति या दिशा का आभास मिलता है। अनेक बार एगिजट पोल लगभग परिणाम के आसपास भी रहे हैं। कई बार गलत भी साबित हुए हैं। इसलिए केवल प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही मत नहीं बनाएं।

भारत में आपिनियन पोल यानी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हो या एगिजट पोल मतदान के बाद का सर्वेक्षण ऐसा कोई वर्ष नहीं जब इस पर जबरदस्त विवाद तथा तू-तू-मैं-मैं न होती हो। मतदान के बहुमत की प्रवृत्ति या दिशा जिस पार्टी या समूह के विरुद्ध दिखाई जाती है यानी जिसके पराजित होने की संभावना व्यक्त होती है वह इसका विरोध करता है। हालांकि विरोध सामान्य या तथ्यों के आधार पर प्रश्न उठाया जाए या कोई तार्किक आपत्ति हो तो समस्या नहीं। अगर किसी एजेंसी या मीडिया संस्थान को आपिनियन पोल या एगिजट पोल करने और उसे सामने लाने का अधिकार है तो संबंधित पार्टियों को भी विरोध करने का। किंतु पिछले कुछ वर्षों से ऐसी सभी एजेंसियां और संस्थाओं को भाजपा द्वारा या सरकार द्वारा प्रायोजित बता कर उसकी साख को भी समाप्त करने का अभियान चलता है।

पश्चिम बंगाल के एगिजट पोल पर तुणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। हालांकि इनमें भी ज्यादातर एजेंसियों ने तुणमूल और भाजपा के मतों मटन एवं सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाया है। हां, ज्यादातर में भाजपा के विजय कि प्रवृत्ति अवश्य दर्शायी गई है। इनमें अंतर इतने महीन हैं कि इन एगिजट पोलों के आधार पर भी आप निश्चयात्मक नहीं मान सकते कि हां यही परिणाम आएगा। केवल एक एजेंसी टुडेज चरणव्या ने भाजपा को तुणमूल से मतों एवं सीटों दोनों में काफी आगे बताया है। तुणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेत्री ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी, उनके मंत्री, सांसद और यहां तक कि टीवी पर बैठने वाले प्रवक्ता व पैनालिट्ट एजेंसियों और चैनलों पर हमले कर रहे हैं। एक एजेंसी ने घोषणा कर दिया कि पश्चिम बंगाल का एगिजट पोल नहीं दिखाएंगे और इसके कारण दिए हैं। आपिनियन पोल और एगिजट पोल पर राजनीतिक दलों तथा कुछ टिप्पणीकारों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों से उनकी विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा है। ऐसा माहौल बना हुआ है मानो सारे एगिजट पोल आज तक



गलत ही साबित हुए हैं। सच ऐसा नहीं है। एगिजट पोल का यह अर्थ नहीं कि वे जितनी सीटें बताते हैं वास्तव में उतने ही आ सकते हैं या आने चाहिए। एगिजट पोल से हमें चुनाव परिणाम का भावी ट्रेंड यानी प्रवृत्ति या दिशा का आभास मिलता है। अनेक बार एगिजट पोल लगभग परिणाम के आसपास भी रहे हैं। कई बार गलत भी साबित हुए हैं। राजनीतिक दलों, एक्टिविस्टों और पत्रकारों के एक वर्ग की अपनी समस्या है। उन्हें केवल एगिजट पोल को नकारना है। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम में एगिजट पोलों के द्वारा दिए गए आंकड़ों से परिणाम भिन्न आए। आवाज यहां तक उठी कि एगिजट पोल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कोई नेता या संगठन दावा करें कि हम इतनी सीटें प्राप्त करेंगे तो उन पर चुनाव प्रक्रिया के बीच आचार संहिता के माध्यम से भी रोक नहीं लग सकती, लेकिन कोई एजेंसी या मीडिया संस्थान ऐसा न करे प्रवक्ता व पैनालिट्ट एजेंसियों और चैनलों पर हमले कर रहे हैं। एक एजेंसी ने घोषणा कर दिया कि पश्चिम बंगाल का एगिजट पोल नहीं दिखाएंगे और इसके कारण दिए हैं। आपिनियन पोल और एगिजट पोल पर राजनीतिक दलों तथा कुछ टिप्पणीकारों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों से उनकी विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा है। ऐसा माहौल बना हुआ है मानो सारे एगिजट पोल आज तक

बावजूद भाजपा लोकसभा में इतनी बड़ी पार्टी बनी कि इसके आसपास कोई दल नहीं है। अधिकतर एगिजट पोल 2024 लोकसभा चुनाव में मुख्यतः तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विफल साबित हुए। अन्य राज्यों के आंकड़े देखें तो उन्हें आप विफल नहीं कर सकते। 2014, 2019 लोकसभा चुनावों में एगिजट पोल और परिणाम की दिशा एक रही।

आपिनियन पोल और एगिजट पोल वर्तमान चुनाव प्रणाली में मतदाताओं की मनःस्थिति समझने का माध्यम है। आपिनियन पोल में आप अलग-अलग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं और गणना करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। केवल किसको मत देंगे और क्यों देंगे यही प्रश्न नहीं होता। मुद्दों, उम्मीदवारों, नेताओं, उनके कार्यों, विकास आदि इतने प्रश्न होते हैं कि उनसे काफी कुछ धरातली वास्तविकता समझा जा सकता है। तब भी आपिनियन पोल परिणाम चुनाव परिणाम की प्रवृत्ति से अलग हो सकते हैं। कारण, ये मतदान पूर्व होते हैं और चुनाव अभियानों से लेकर मतदान तक लोगों का मन बदल सकता है। वैसे भी अब आचार संहिता लागू होने के बाद आपिनियन पोल नहीं दिखाया जा सकता। सर्वेक्षण में पारदर्शिता भी अनुसार अवश्य एगिजट पोल विफल हुए, भाजपा बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई।

पूछा और उनमें किन-किन क्षेत्रों से और किस श्रेणी के लोग थे। आपके सर्वेक्षण करने का तरीका क्या था आदि आदि। पहले मतदान केंद्र के बाहर ही एजेंसियां अपना छाया मतदान पेटी लगाती थीं जिसमें निकलने वाले लोग मत डालते थे। बाद में लैपटॉप और टैब से यह काम किया जाने लगा। जहां लैपटॉप टैब नहीं लगा सकते वहां मतदान कर निकलने वालों से पूछ कर नोट किया जाता है या ऑडियो विजुअल टेप रहता है। अगर ईमानदारी और पेशेवर तरीके से एगिजट पोल हो तथा उनमें आए तथ्यों का आंकड़ों में ठीक से आकलन जाए तो परिणाम की दिशा अवश्य सामने आ जाएगी। चाहे आपिनियन पोल हो या एगिजट पोल उनमें आरंभ से ही ईमानदारी और पेशे की वास्तविक समझ की आवश्यकता है। फिर आपके पास सर्वेक्षण आ गए और उनको विफल नहीं कर सकते। 2014, 2019 लोकसभा चुनावों में एगिजट पोल और परिणाम की दिशा एक रही।

चुनाव विश्लेषण : नतीजों से पहले परिणाम की जंग

एगिजट पोल की सटीकता पर उठते गंभीर सवाल



चुनौती

रिश शंकर

स्वतंत्र पत्रकार

चुनाव खत्म होते ही देशभर में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की होती है, तो वह है एगिजट पोल। वोटिंग खत्म होने के कुछ घंटों बाद टीवी चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर सीटों के अनुमान आने लगते हैं। लोग यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है। राजनीतिक दल भी एगिजट पोल पर नजर रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एगिजट पोल पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? दरअसल, भारतीय चुनावों में एगिजट पोल के परिणाम अक्सर वास्तविक नतीजों से अलग पाए जा रहे हैं, जिससे उनकी सटीकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले कुछ चुनावों का इतिहास दर्शाता है कि कई बार एगिजट पोल के अनुमान गलत साबित हुए हैं। पश्चिम बंगाल इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां 2021 और 2016 के विधानसभा चुनावों में एगिजट पोल ने कांटे की ठट्कार या अलग परिणाम दिखाए थे, जबकि तुणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। दरअसल, कई बार एगिजट पोल और असल नतीजों में मामूली अंतर होता है। लोगों के मन में सवाल है कि एगिजट पोल सटीक क्यों नहीं हो पाते हैं। करीब 100 करोड़ के मतदाताओं वाले देश में चंद हजार लोगों से बातचीत के आधार पर एगिजट पोल का सर्वे किया जाता है। एगिजट पोल में शामिल होने वाला मतदाता क्या सच बोल रहा है या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में कई पोलिंग बूथ होते हैं। एगिजट पोल का सर्वे करने वाली एजेंसियां क्या सभी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं से बात करती हैं या कुछ एक बूथ पर ही जाती हैं। हर पोलिंग बूथ और क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान अलग-अलग होता है। पिछले तीन दशक में ऐसे कई मौके आए हैं जब एगिजट पोल ओंथे मुंह निरा है। बता दें, एगिजट पोल की शुरुआत भारत में सबसे पहले 1970 अंत और 1980 के दशक के शुरू में हुई थी। ये शुरुआती पोल बहुत ही बुनियादी थे और कुछ अवर्णी संगठनों और मीडिया घरानों द्वारा संचालित किए गए थे। ये काफी हद तक प्रयोगात्मक थे और परिष्कृत नमूनाकरण तकनीकों और डेटा विश्लेषण उपकरणों की कमी के कारण हमेशा सटीक नहीं होते थे। 1990 के दशक में एगिजट पोल की संख्या और दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के दशरीकरण और निजी टेलीविजन चैनलों के आगमन के साथ, मीडिया घरानों ने राजनीतिक कवरेज और विश्लेषण में अधिक निवेश करना शुरू कर दिया। इस अवधि में विशेषीकृत मतदान एजेंसियों का उदय भी हुआ। अपनी बदती लोकप्रियता के बावजूद, इस समय के दौरान एगिजट पोल को अक्सर उनकी अशुद्धियों और मतदाता व्यवहार पर संभावित प्रभाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि, 2000 के दशक की शुरुआत में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया पर एगिजट पोल के प्रभावित प्रभाव पर ध्यान देना शुरू किया। 1998 में आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने से बचने के लिए मतदान के कुछ चरणों के दौरान एगिजट पोल के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, मतदान एजेंसियों ने अधिक परिष्कृत तरीके अपनाना शुरू कर दिया। कंप्यूटरीकृत डेटा संग्रह और विश्लेषण ने एगिजट पोल की सटीकता और विश्वसनीयता में कुछ हद तक सुधार अवश्य हुआ। इस अवधि में भारत में अध्ययन के एक सम्मानित क्षेत्र के रूप में सेफोलॉजिस्ट का उदय भी देखा गया। स्पष्ट है, जब नजर सेंतुलित हो, तभी सच साफ़ दिखता है-एगिजट पोल को लेकर यही सबसे बड़ा समाधान है। ये न पूरी तरह गलत हैं, न पूरी तरह सही- इनका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे देखते हैं। यदि इन्हें संकेतक माना जाए, तो ये उपयोगी हैं, लेकिन यदि अतिविमर्श मान लिया जाए, तो क्षम पैदा करते हैं। 2026 के इन महत्वपूर्ण चुनावों में जरूरी है कि हम आंकड़ों की चमक से प्रभावित होने के बजाय वास्तविकता की प्रतीक्षा करें। क्योंकि लोकतंत्र की सच्ची रक्षाएं वहीं होती हैं जो मतपेटियों से निकलती हैं, न कि वह जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है।



चिंतन

चरणजीत 'चरण'

वरिष्ठ पत्रकार

भारत में चुनाव विश्लेषण (एगिजट पोल) सरकार के बदलने विधायक, सांसद, बदलने की सम्भावना प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि भारत का एगिजट पोल अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह से उसका विश्लेषण करने गुना-भाग करने और परिणाम घोषित होने से पहले अपने आंकड़ों पर डिबेट करने का एक माध्यम है। भौतिक रूप से बेशक इसका कोई फायदा नज़र न आता हो, लेकिन तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया के द्वारा भी लोकतंत्र की मज़बूती का मार्ग प्रस्तर होता है। जो लोग चुनाव में थोड़े निष्क्रिय रहते हैं वो भी अपने पसंद के उम्मीदवार और पार्टी तय कर लेते हैं। इन सभी चुनावी प्रक्रियाओं में वोटिंग से लेकर रिजल्ट आने तक के चार पांच दिनों में मतदाता कहीं थका हुआ या ठगा मासूस ना करे तो उसके लिए चुनाव वाले दिन या

उससे एक दो दिन आगे एगिजट पोल की व्यवस्था है। एगिजट पोल की के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाती है कि मतदाता का रुझान किस तरफ है। वह वर्तमान सरकार को बदलना चाहता है या उसे एक मौक़ा और देना चाहता है। चुनावी विश्लेषक या सेफोलॉजिस्ट एगिजट पोल के द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के माध्यम से मतदाता के मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय मतदाता अपने सात दशकों के लोकतंत्र में इतना परिपक्व हो गया है कि वह अंतिम समय तक किसी को भनक नहीं लगने देता कि उसका मत कहां जाएगा। शायद यही कारण है कि कई बार एगिजट पोल बुरी तरह उलट जाते हैं। एगिजट पोल के इतिहास में ऐसा अनेक बार हो चुका है जब अधिकतर एगिजट पोल जिधर इशारा करते हैं परिणाम उसके बिल्कुल उलट होता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे समाज में ये संभव ही नहीं है कि कोई विश्लेषक एगिजट पोल के सटीक परिणाम तक पहुंच सके। इसके पीछे अनेक कारण हैं। जहां एक विधानसभा में मतदाताओं की संख्या तीन से चार लाख तक होती है वहां पांच सौ या हजार लोगों की

पसंद के आधार पर पूरी विधान सभा का विश्लेषण करना कठिन है। इसके अतिरिक्त



भारतीय मतदाता इतना परिपक्व हो गया है कि वह अंतिम समय तक किसी को भनक नहीं लगने देता कि उसका मत कहां जाएगा।

भारत में भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, ख़ू, पुरुष, किसान, मजदूर, युवा, नौकरी-पेशा बेरोजगार, गांव, शहर में बंटे मतदाता की समस्याएं और उसके विचार अलग हैं। इसी

आधार पर लोग वोट भी करते हैं। इसलिए चुनाव के पश्चात कुछ लोगों की राय के आधार पर हार-जीत का विश्लेषण करना चुनौती पूर्ण रहता है। पिछले कई वर्षों के एक्सिटपोल के आंकड़ों पर यदि नज़र डाले तो जहां दो पार्टियों में कांटे का मुकावला होता है वहां 1% का मतान्तर भी आंकड़े को 40/60 में बदल देता है। अगर यही अनुपात तीन चार प्रतिशत तक चला जाए तो एक पार्टी को दो तिहाई बहुमत तक मिल जाता है ऐसी स्थिति में किसी भी सेफोलॉजिस्ट के लिए कुछ सैंपल साइज के आधर पर सटीक आंकड़े देना बहुत कठिन कार्य है। 2023 और 2024 के छत्तीसगढ़ और हरियाणा के चुनाव इसका सटीक उदाहरण है। 2023 के छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव में जहां लगभग सभी एगिजट पोल जिस पार्टी के पक्ष में थे उसे हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी एक्सिटपोल जिस रूलिंग पार्टी के विपरीत जा रहे थे उसी तीसरी बार बहुत मिला। कई सेफोलॉजिस्ट का मानना है कि भारत में जातीय और धार्मिक रूप से पिछड़े, दबे, कुचले मतदाता अपनी राय सार्वजनिक करने से डरते हैं। या उनके मन

में थोड़ी हिचकिचाहट रहती है। इस भाव को सर्पिल ऑफ साइलेंस कहा जाता है। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका सटीक उदाहरण है जहां अधिकतर पोल महाराष्ट्रबंधन की जीत का पूर्व आंकलन नहीं कर सके और परिणाम परिणाम एगिजट पोल के बिलकुल विपरीत निकले। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अक्सर दलित और पिछड़े मतदाता अंतिम क्षण तक खुलकर बात नहीं कर पाते। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि एगिजट पोल मतदाता की मनःस्थिति का आंकलन नहीं है। बल्कि संभावित परिणाम का मात्र एक चित्र है। एक सेफोलॉजिस्ट समाज के भीतर चल रहे विचार, समस्या और संभावनाओं का आंकलन करता है। आंकड़ों को सटीकता तक पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। क्योंकि भारत का विविधताओं से भरा समाज व मर्यादाओं में बंधी संस्कृति शापद कभी एक मतदाता में देगी ये इजाजत नहीं देगी कि वह अपने मत की गोपनीयता को भंग कर दे। भारत में मतदाता की चुप्पी एक तरह से पुरे चुनाव को व्यावहारिक और रोमांचक बनाती है। और यह चुप्पी बनी रहनी चाहिए यही लोकतंत्र के हित में भी है।

रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से कयासों के भंवर में दल



दृष्टिकोण

अम्बरेश प्रजापति

स्वतंत्र स्तंभकार

पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में इस बार का मतदान प्रतिशत एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, जिसने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। 23 और 29 अप्रैल को संपन्न हुए दो चरणों के इस महाकुंभ में जनता ने जिस तरह दिल खोलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वह इस बात का साक्ष्य है कि बंगाल का मतदाता अपने भविष्य को लेकर कितना जागरूक और मुखर है। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और लंबी-लंबी कतारें महज एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि एक बड़े बदलाव या एक बड़े समर्थन की मौन महाकुंभ थीं, जिसका असली खुलासा अब 4 मई को होगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जहां अपनी 'माटी और मातृ' की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए एड़ी-

चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी ने बंगाल में भगवा परचम लहराने के लिए अपनी पूरी सांगठनिक शक्ति झोंक दी है। इस बार के चुनावों में मतदान का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना दोनों ही खेमों के लिए कशमकश और कयासों का केंद्र बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में यह बहस छिड़ गई है कि आखिर यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किसके हक में जाएगा। क्या यह सत्ता विरोधी लहर का प्रतीक है या फिर मौजूदा सरकार के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। चुनाव के संपन्न होते ही बंगाल की आबोहवा में दावों और प्रतिदावों का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी का मानना है कि महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं, ग्रामीण विकास और स्थानीय अस्मिता के मुद्दे ने जनता को घरी से बाहर निकाला है। उनका तर्क है कि जब जनता बड़े पैमाने पर वोट करती है, तो वह अक्सर स्थिर सरकार और लोकप्रिय नेतृत्व के पक्ष में होता है। दूसरी ओर, बीजेपी के खेमे में भी उस्तहा की कोई कमी नहीं है। उनके अनुसार, यह भारी मतदान परिवर्तन की आकांक्षा का सूचक है। बीजेपी का मानना है



पोल ऑफ पोलस की स्थिति इतनी धुंधली है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यह अनिश्चितता ही इस चुनाव के रोमांच को बढ़ा रही है।

आक्रोश ने उन्हें मतदान केंद्रों तक खींचा है। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बृथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक, हर कोई अपनी-अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो दिख रहा है,

लेकिन भीतर ही भीतर एक अनजाना डर और संशय भी बना हुआ है। बंगाल का यह चुनाव कई मायनों में अनूठा। अब एगिजट पोल के आंकड़ों ने इस कशमकश को और भी बढ़ा दिया है। विभिन्न सर्वेक्षणों में जहां कुछ एजेंसियां बीजेपी को बहुमत के करीब दिखा रही हैं, वहीं कुछ अन्य टीएमसी की वापसी की भविष्यवाणी कर रही हैं। 'पोल ऑफ पोलस' की स्थिति भी इतनी धुंधली है कि किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी होगी। यह अनिश्चितता ही इस चुनाव के रोमांच को द्विगुणित कर रही है। जब 4 मई को मतपेटियां खुलेंगी और ईवीएम के बटन दवेंगे, तब पता चलेगा कि जनता ने वास्तव में किसे अपना भाग्य विधाता चुना है। क्या ममता बनर्जी की 'हैट्रिक' के बाद चौथी बार सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी या फिर सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल की सत्ता के गलियारों में पहली बार प्रवेश करेगी। इस बात के चुनावों में निर्वाचन आयोग की भूमिका और सुरक्षा इंतजामों की भी चर्चा लाजिमी है। छिटपुट हिंसा की घटनाओं को छोड़ दें, तो मतदान की प्रक्रिया को सुचारू

रूप से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे पार कर लिया गया है। मतदाता सूची में किए गए संशोधनों और विशेष सर्वेक्षणों के कारण इस बार मतदाताओं की संख्या में जो बदलाव आए, उसने भी प्रतिशत के आंकड़ों को प्रभावित किया है। लेकिन इन तकनीकों पहलुओं से परे, सबसे महत्वपूर्ण पहलू मतदाता का वह मौन संकल्प है जो उसने ईवीएम के अंदर दर्ज किया है। बंगाल की जनता अपनी चुप्पी के लिए जानी जाती है और अक्सर यह चुप्पी बड़े-बड़े दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य को धाराशायी कर देती है। अंततः बीजेपी और टीएमसी के बीच की यह कसमकश इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र में कोई भी पद स्थायी नहीं है और जनता ही सर्वोपरि है। तब तक कयासों का बाजार गर्म रहेगा, चर्चाएं चलती रहेंगी और धड़कनें बढ़ी रहेंगी। बंगाल ने अपना फैसला सुना दिया है, बस उसका सार्वजनिक होना बाकी है। सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, वह तो वक्त की कृपा है, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले ने यह जरूर साबित कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है।

पारदर्शिता से काम करें सर्वे कंपनियां



उम्मीद

योगेश कुमार सोनी

वरिष्ठ पत्रकार

ते दशकअर में अब एगिजट पोल्स पर से लोगों का भरोसा उठता हुआ दिखने लगा है। कारण यह है कि एगिजट पोल्स सटीक तरीके से चुनाव नतीजों के साथ मेल नहीं खा रहे। पिछले कुछ चुनावों में कुछ एगिजट पोल तो बिल्कुल ही गलत साबित हुए हैं। जैसा कि अभी हाल ही में पांच राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो सबकी निगाह यहां बनी हुई है। हाल ही में तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल हुए चुनावों के एगिजट पोल जो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस कारण भी सबके सामने हैं, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले केवल विधानसभा या लोकसभा एक हजार लोगों से राय लेते थे

और उससे ही उस सीट की जीत व हार तय करते थे, लेकिन अब पांच व दस हजार लोगों से राय लेकर भी एगिजट पोल्स सटीक नहीं बैठ रहे। और ज्ञात हो कि चुनाव संपन्न होने के बाद ही सर्वे कंपनियां अपना रिजल्ट बता दी थीं, लेकिन अब पहले चरण में हुए चुनाव से ही अपने रिजल्ट रख देते हैं व इसके अलावा अब आरोप यह लगने लगे कि सर्वे कंपनियों को किसी भी पार्टी के पक्ष में हवा बनाए रखने के लिए गलत रिपोर्ट देने लगी जिससे की पार्टी को फायदा हो। दूसरा पहलू यह है कि एगिजट पोल के सर्वे इस बात पर आधारित होते हैं कि वोटिंग करके मतदान केंद्रों से निकल रहे लोग सही जवाब देंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ मतदाता वास्तव में झिझकते हैं व कुछ गोलमोल जवाब देते हैं तो कुछ गलत भी बताते हैं। समझा यह भी जाना है कि मतदाता दबाव, डर, सामाजिक परिस्थितियों के चलते खुलकर अपने मत का खुलासा नहीं करते। एगिजट पोल करने वाली एजेंसियां सभी मतदान केंद्रों को कवर नहीं कर पातीं। रैंडम सैपलिंग की कमी और छोटी सैपल साइज के कारण भी परिणाम गलत हो सकते हैं। अक्सर सर्वे एजेंसियां वोट शेयर का अनुमान तो सही लगा लेती हैं, लेकिन वह वोट किस सीट पर कितना प्रभाव होगा इसका सटीक अनुमान नहीं लगा पातीं। कई बार एगिजट पोल का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी माहौल बनाने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षकों के पक्षपातपूर्ण रवैये और सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में झुकवा होने के कारण भी परिणाम वास्तविक नतीजों से अलग हो सकते हैं। मतदान के अंतिम चरणों या वोट डालने से ठीक पहले के रुझान सर्वे में कैद नहीं हो पाते जिससे अंतिम परिणाम सर्वे में बताए हुए परिणामों के व विपरीत दिखते हैं। यह बात लगातार दिखने लगी और इस वजह से सर्व की गंभीरता कम होने लगी। एक रिजल्ट के अनुसार भारत में पिछले बार व्षकों में 833 सर्वेक्षणों जिसमें 386 पूर्व मतदाता पोल यानी ओपिनियन पोल व 447 एगिजट पोल शामिल हैं जिसमें लगभग तीन तिहाई सर्वेक्षणों ने सही विजता पार्टी का अनुमान लगाया। एगिजट पोल की सफलता दर भारत में लगभग आरसी प्रतिशत बताई गई है जाती रही है जबकि पूर्व-मत सर्वेक्षण की सफलता दर सत्र प्रतिशत से भी ज्यादा थी। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में एगिजट पोलों का सटीकता काफी सीमित मानी जाती थी लेकिन अब सबसे ज्यादा अविश्वास हमारे देश में उत्पन्न होने लगा है। एक कदावत भी है कि अति दूर चीज की बुरी होती है इसलिए सर्व कंपनियों की कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान खड़े होने से जनता मन में एगिजट पोल्स की गंभीरता खत्म होने लगी। सर्वे कंपनियां लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर सर्व कराती है जिससे चुनाव से पहले एक रोमांच पैदा होने लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यदि विश्वसनीय को बनाए रखना हो तो सर्व कंपनियों को अपना पैटर्न बदलना होगा जिसके लिए उनका काम चलता रहे साथ ही उनके सर्व पर विश्वसनीयता भी बनी रहे। अवस्था फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, चेक गणराज्य में भी निर्विवाद स्थल पर एगिजट पोल भारत में प्रतिबिंबित हो हो जाए। चूंकि इन देशों का मानना है कि किसी भी चुनाव का पहले से रिजल्ट से देश या राज्य में एक नकारात्मकता फैलती है और जो भी निर्णय होगा वो नेता या पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। वहीं इससे किसी भी नेता या पार्टी जीतने व हारने को लेकर सट्टेबाज करोड़ों का सट्टा लगाने में जिससे अख्यवस्था फैलती है एक नजरिये से यह सही लगता है सर्व नहीं होना चाहिए चूंकि निर्णय की जिज्ञासा का बना रहना जरूरी है। इसलिए सर्वों से हो तो इसकी विश्वसनीयता बनी रही या फिर न हो।

एगिजट पोल लोकतंत्र में रुझान समझने का माध्यम हैं, लेकिन घटती सटीकता व पक्षपात के आरोपों ने भरोसा कमजोर किया है। विश्वसनीय बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, बेहतर सैपलिंग और निष्पक्षता जरूरी है, अन्यथा इनकी उपयोगिता पर सवाल उठते रहेंगे।



कठिन समस्याएं अब न होंगी

क्योंकि सच्ची सहेली में हैं **67** खास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां जो मुश्किल तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करें।

24x7 Helpline: 77106 44444 • www.sachhisaheli.in

67 दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बना ‘सच्ची सहेली’ आयुर्वेदिक टॉनिक एवं टेबलेट्स

Helps in:

- कठिन दर्द
- चिड़चिड़ापन
- थकान
- कमजोरी
- कमर कटना
- इम्यूनिटी



खबर संक्षेप

सर्जियो गोर से नहीं मिले पीएम बालेन शाह काठमांडू। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने डॉनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर से मुलाकात नहीं की। सर्जियो गोर नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत हैं और उनका दौरा बालेन शाह से मुलाकात के बगैर ही खत्म हो गया है। सर्जियो गोर गुरुवार को छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिनों के दौरे पर काठमांडू पहुंचे थे और अमेरिकी टीम ने बालेन शाह से मुलाकात की काफी कोशिशें की थी। इससे पहले वे अमेरिका के सहायक विदेश सचिव समीर पॉल कपूर से भी नहीं मिले।

नित्या रमन लड़ रही लॉस एंजिल्स मेयर पद का चुनाव
लॉस एंजिल्स। अमेरिका में लॉस एंजिल्स के मेयर पद के लिए दो जून को चुनाव होने वाले हैं। इस रेस में भारतीय मूल की नित्या रमन भी अहम दावेदार बनकर उभर रही हैं। नित्या रमन का जन्म केरल के तमिल परिवार में हुआ था। छह साल की उम्र में उनका परिवार अमेरिका के लुडिसियाना में बस गया। 22 साल की उम्र में वह अमेरिकी नागरिक बन गईं। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। वह डिस्ट्रिक्ट 4 का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

लुपथांसा एयरलाइन ने खोजी गुम हुई ऑस्कर ट्रॉफी


लंदन। जर्मन एयरलाइन लुपथांसा ने कहा कि उसने रूसी फिल्म निर्माता पाशा तालनकिन को ऑस्कर पुरस्कार प्रतिमा का पता लगा लिया है, जो न्यूयॉर्क के जेएफके हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा संभावित हथियार के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद गुम हो गई थी। इस साल मार्च में अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 'मिस्टर नोबडी ऑगस्ट पुतिन' के सह-निर्देशक तालनकिन बुधवार को न्यूयॉर्क से फ्रैंकफर्ट की अपनी यात्रा के दौरान ट्रॉफी के गायब हो जाने के बाद सदमे में थे।

म्यांमार दौरे पर पहुंचे नौसेना प्रमुख सैन्य अधिकारियों संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

■ क्षमता विकास क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
एजेंसी ►► नेवीडी

भारत की समुद्री रणनीति को मजबूत करने के लिए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी म्यांमार

के चार दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। यह दौरा 2 मई से 5 मई तक चलेगा। इस यात्रा का मकसद भारत और म्यांमार के बीच समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिलिप ग्रीन का अलगाववादियों को कड़ा संदेश

भारत की अखंडता से कोई समझौता नहीं प्रदर्शन की आड़ में गलत बातें बर्दाश्त नहीं

एजेंसी ►► नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं पर ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा और कड़ा बयान दिया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त (राजदूत) फिलिप ग्रीन ने साफ कर दिया है कि उनका देश भारत की क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है। उन्होंने अलगाववादी ताकतों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते वहां

शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो हो सकते हैं, लेकिन अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। राजदूत फिलिप ग्रीन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और खुफिया एजेंसियां भारत की चिंताओं को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। उनकी बहुसांस्कृतिक, खुफिया, पुलिस और विदेश नीति से जुड़ी एजेंसियां इस मुद्दे पर लगातार आपस में बैठकें कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता में विश्वास करते हैं और अलगाववादी तत्वों से उनका कोई भी लेना-देना नहीं है।

बदजुबानी पर उतरा अमेरिका, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरानी नेतृत्व पर तीखा हमला किया

ये ‘गटर के पाइप में रहने वाले चूहे’, ईरान बोला- यह युद्ध में हारने वाले की भाषा है

बेसेंट ने ईरानी नेतृत्व के बारे में कहा कि वे अंधेरे में बैठे हैं और उन्हें यह नहीं पता कि अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है। डॉलर की कमी है। भोजन और पेट्रोल का सीमित मात्रा में वितरण हो रहा है और पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी

ईरान की तीखी प्रतिक्रिया, सब जानते हैं कि आप और आपके बाँस युद्ध हार चुके

नाकाबंदी से ईरान को हुआ 4.8 अरब डॉलर का नुकसान

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेटाजन ने दावा किया है कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी और कार्रवाई से ईरान को तेल के राजस्व में लगभग 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के आकलन के अनुसार, इस क्षेत्र में अमेरिका की कार्रवाई के कारण ईरान को तेल से होने वाली आय में करीब पांच अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह नुकसान इकट्ठा हुआ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से समुद्र में जो कार्रवाई की जा रही है, उससे ईरान का समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात बाधित हो गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी सीन पॉर्नेल ने पेटाजन के कार्यवाहक प्रेस सचिव जोएल वाल्डेन के बयान का हवाला दिया।



डोनाल्ड ट्रंप मोजताबा खामेनेई

ट्रंप की चेतावनी, पागलों के हाथ में नहीं दे सकते परमाणु बम

ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कई लहजे में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि वे इसका इस्तेमाल सबसे पहले इजराइल पर करेंगे, फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप पर, और अगला नंबर हमारा होगा। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं रहने दे सकते। ट्रंप ने कहा कि वे समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन में इससे संतुष्ट नहीं हूँ।

ट्रंप ने संसद को दी जानकारी ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संसद को बताया कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध खत्म हो गया है। ट्रंप ने ईरान युद्ध की 60 दिनों की कानूनी समयसीमा खत्म होने के बाद संसदों को यह जानकारी दी। ट्रंप ने सांसदों को लिखे एक पत्र में कहा कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई शत्रुता अब समाप्त हो चुकी है। यह कदम ईरान युद्ध को जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत के विवाद को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। अमेरिका में 1973 में पारित 'चार पावरर्स रिजॉल्यूशन' के तहत राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई की सूचना कांग्रेस को देने के बाद 60 दिनों के भीतर उसे समाप्त करना होता है, जब तक कि कांग्रेस आगे की कार्रवाई को मंजूरी न दे। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था।

कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा ने माना ‘खालिस्तानियों’ से सुरक्षा को खतरा, हिंसा को बढ़ावा दे रहे



एजेंसी ►► ओटावा

कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा (सीएसआईएस) ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में माना गया है कि खालिस्तानी तत्वों से कनाडा को खतरा पैदा हो रहा है। सीएसआईएस की 2025 की रिपोर्ट कनाडा की संसद में पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां लगातार एक हिंसक चरमपंथी एजेंडा को बढ़ावा देती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे चरमपंथी समूहों की गतिविधियां कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं।

एअर इंडिया हमले में खालिस्तानी शामिल

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल एअर इंडिया की उड़ान 182 में बम विस्फोट की 40वीं बरसी थी, जिसके संदिग्ध कनाडा आधारित खालिस्तानी चरमपंथी समूहों के सदस्य थे। यह कनाडा के इतिहास का अब तक का सबसे घातक आतंकवादी हमला माना जाता है। इसमें 329 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर कनाडाई नागरिक थे। 2025 में कनाडा में खालिस्तानी समूहों से जुड़ा कोई हमला नहीं हुआ। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी के कारण इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि भारत अपनी अंदरूनी स्थिरता के लिए खतरों का सामना करता है।

कार्नी के पीएम बनने के बाद संबंधों में सुधार

यह रिपोर्ट 2025 की खुफिया आकलन पर आधारित है। लेकिन हाल के समय में इसमें बदलाव के संकेत भी मिले हैं। पीएम मार्क कार्नी के कार्यभार संभालने के बाद कनाडाई अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें लगता है कि भारत वर्तमान में कनाडा की धरती पर किसी हिंसक अपराध या खतरे से जुड़ा नहीं है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के प्रमुख माइक ड्यूहम ने भी कहा कि कनाडा के लिए किसी विदेशी एजेंट से कोई सीधा खतरा साबित नहीं हुआ है।

भारत तंजानिया के बीच बैठक व्यापार 9 बिलियन डॉलर पार ऊर्जा क्षेत्र में समझौते पर बल

एजेंसी ►► नई दिल्ली

भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति बैठक का 5वां सत्र तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार 9 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो बढ़ती साझेदारी का संकेत है। बैठक के दौरान ऊर्जा उप-क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक समझौता ज्ञापन की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत ने परामर्श, क्षमता निर्माण, परियोजना प्रबंधन और ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ-साथ हाइब्रिड ऊर्जा समाधानों में सहयोग की पेशकश की।



कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा
बैठक में व्यापार मेलों में भागीदारी, कृषि वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, आवास और शहरी विकास तथा पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। टैरिफ, पौध संरक्षण उपायों और नियामक प्रक्रियाओं से जुड़े बाजार पहुंच के मुद्दों पर भी विचार किया गया।

अगली बैठक नई दिल्ली में
बैठक के समापन पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, जारी पहलों के तेज क्रियान्वयन और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

कूज दुर्घटना: दिल्ली के एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत

एजेंसी ►► नई दिल्ली।

मध्यप्रदेश में गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गए दिल्ली के एक परिवार की यात्रा नर्मदा नदी के बरगी जलाशय में कूज के पलटने के कारण दर्दनाक हादसे में बदल गई। इस दुर्घटना में परिवार के छह में से तीन

सदस्यों की मौत हो गई। परिजन के अनुसार, दिल्ली कैंट क्षेत्र का मैसी परिवार मंगलवार को जबलपुर में एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गया था। कार्यक्रम के बाद उन्होंने दिल्ली लौटने से पहले घूमने का फैसला किया। बृहस्पतिवार रापे, परिवार करीब 40 यात्रियों के



साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित कूज पर सवार हुआ, जो बरगी बांध पर तेज हवाओं और ऊंची

लहरों के कारण असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में मरीना (39), उनका चार वर्षीय बेटा त्रिशन उर्फ जहां, मरीना की मां मधुर मैसी (62) की मौत हो गई। वहीं मरीना के पति प्रदीप, 14 वर्षीय बेटी सिया उर्फ पीहू और मरीना के पिता जूलियस मैसी (65) बच गए।

‘ऑपरेशन ग्लोबल हंट’: सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी

यूएई से भारत लाया गया भगोड़ा कमलेश पारेख

एजेंसी ►► नई दिल्ली

भारत सरकार के ‘ऑपरेशन ग्लोबल हंट’ के तहत विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में अंजाम दी गई। पारेख के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, जिसके आधार पर उसे यूएई में ट्रैक कर (यूएई) से भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया है। 1 मई को पारेख को भारत लाया गया, जहां दिल्ली पहुंचते ही सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई

कई बैंकों के साथ की धोखाधड़ी

जांच एजेंसियों के अनुसार, कमलेश पारेख पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है। इस घोटाले में देश के कई बैंकों के समूह को भारी नुकसान हुआ, जिसकी अगुवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) कर रहा था। अनुमान है कि इस मामले में सैकड़ों करोड़ रुपये की रकम का दुरुपयोग किया गया। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि पारेख ने अन्य प्रमोटरों और निदेशकों के साथ मिलकर बैंक से लिए गए फंड को विदेशों में स्थित कंपनियों के जरिए डायवर्ट किया।

150 से अधिक वांछित अपराधियों का भारत लाया गया

सीबीआई, जो भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है, ‘भारतपोल’ प्लेटफॉर्म के जरिए देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। इसी सहयोग का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से 150 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। यह ताजा कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है।

पारेख का कई देशों में कारोबार

आरोपी ने यूएई सहित कई देशों में फैले अपने कारोबारी नेटवर्क का इस्तेमाल कर इस धोखाधड़ी की अंजाम दिया। जांच एजेंसियां अब उससे पृथक्ता कर पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने में जुटी हैं।